

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण

कंपनी लिमिटेड

बी.

आदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 684)

मार्च 03,2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

विजली दीर्घकालिक विजली खरीद समझौते (पी. पी. ए.)

विजली उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति-नए कोयले में बदलाव

नया कोयला वितरण नीति, 2007 (एन. सी. डी. पी., 2007) वितरण नीति, 2013 (एन. सी. डी. पी. 2013)-'कानून में परिवर्तन' राहत मुआवजे का दावा-संचालन मानदंड आयोजित किए गए: एनर्जी वॉचडॉग मामले के साथ-साथ अडानी राजस्थान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून में बदलाव के कारण, उत्पादन कंपनियां मुआवजे की हकदार हैं ताकि पार्टी को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल किया जा सके जैसे कि कानून में ऐसा बदलाव नहीं हुआ था-अगर कानून में बदलाव नहीं हुआ होता, तो उत्पादन कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/कोयला कंपनियों द्वारा आश्वासन के अनुसार आपूर्ति की हकदार होतीं।

ईंधन आपूर्ति समझौता (एफ. एस. ए.)-यह प्रस्तुत करना कि जब बोली लगाने वाले

अपनी बोलियाँ प्रस्तुत की, यह एक जोखिम था जो उन्होंने जानबूझकर लिया था, बिना किसी तथ्य के है-उत्पादक कोयले की कीमत में वृद्धि के आधार पर या बल दुर्घटना के आधार पर मुआवजे का दावा नहीं कर रहे हैं।

-

उनके दावे, वास्तव में, कानून में परिवर्तन के आधार पर हैं, जिसे इस न्यायालय ने, एनर्जी वॉचडॉग के मामले के साथ-साथ अडानी राजस्थान मामले में, कानून में परिवर्तन के आधार पर बरकरार रखा है।

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) का यह तर्क कि अडानी राजस्थान का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अडानी राजस्थान मामले में, राजस्थान राज्य ने कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया था और यह कि यह एफ. एस. ए. का मामला नहीं था, इसमें कोई सार नहीं है-वर्तमान मामले में भी, एन. सी. डी. पी. 2007 ने मानक मूल्य की ईंधन/कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया था -

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन सिद्धांत कहा गया है-निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी नं. 1 - ए. पी. एम. एल. कानून में परिवर्तन के आधार पर खड़ा है-डिस्कॉम्स, जो राज्य के साधन हैं, से सरकार के रुख के विपरीत बहस करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जनरेटर कानून में बदलाव के आधार पर खुले बाजार से आयात या खरीदे जाने के लिए आवश्यक कोयले के लिए गुजरने के हकदार होंगे-डिस्कोम्स द्वारा लिया गया रुख कि चूंकि उत्पादन करने वाली कंपनियों को सीआईएल/कोयला कंपनियों द्वारा दायित्व की पूर्ति न करने के कारण नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें सीआईएल/कोयला कंपनियों के खिलाफ कानून में उनके लिए उपलब्ध उपचार के लिए पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। अनुचित-- दावा एन. सी. डी. पी. 2013 द्वारा एन. सी. डी. पी. 2007 के परिवर्तन पर आधारित है, जो निर्विवाद रूप से 'कानून में परिवर्तन'-क्षतिपूर्ति-'कानून में परिवर्तन' मुआवजे शब्द द्वारा कवर किया गया है।

न्यायिक समीक्षा-विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णय की-केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.), केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (सी. ई. आर. सी.) और बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.)-अंतः - ये निकाय क्षेत्र के विशेषज्ञों से बने निकाय हैं, न्यायालयों को क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए और जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक नियमों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं।

प्रावधान या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित होते हैं या वे प्रत्यक्ष रूप से मनमाने और अवैध होते हैं, न्यायालय के लिए अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के साथ प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।

विद्युत अधिनियम, 2003-उद्देश्य और उद्देश्य-विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के प्रमुख कारणों में से एक गिरावट थी।

राज्य विद्युत बोर्डों के निष्पादन में-यह देखा गया है कि कई मामलों में, नियामक निकाय और अपीलीय मंच द्वारा पारित समवर्ती आदेशों पर हमला किया जाता है-इस तरह की मुकदमेबाजी, वास्तव में, विद्युत अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देगी।

विवेक नारायण शर्मा बनाम। भारत संघ 2023 एससीसी

ऑनलाइन एससी 1-फॉलो किया गया।

एनर्जी वॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80 और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम। अदानी पावर

राजस्थान लिमिटेड और एक अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी

697 पर भरोसा किया।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) और एक अन्य वी. अडानी पावर लिमिटेड और अन्य (2019) 5 एससीसी 325: [2019] 4 एस. सी. आर. 487; रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर

सीमित वी।

महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2019) 3 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड।

एससीसी 352: [2019] 1 एस. सी. आर. 886; केंद्रीय भंडारण निगम बनाम। अदानी बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र

लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी

आयोग और अन्य (2022) 4 एस. सी. सी. 657; तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड v. पीपीएन

पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2014) 11

एस. सी. सी. 53 [2014] 4 एस. सी. आर. 667 और नाभा पावर लिमिटेड

(एन. पी. एल) वी. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और एक अन्य (2018) 11 एस. सी. सी. 508: [2017] 14

एस. सी. आर. 301-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 14 एससीसी 80

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2017] 14 एससीआर 301

पैरा 43

(XXVI)

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii)

[2019] 4 एससीआर 487

संदर्भित किया गया है

(2022) 4 एस. सी. सी. 657

पैरा 45

(ix)

संदर्भित किया गया है

[2014] 4 एससीआर 667

पैरा 45

(ix)

संदर्भित किया गया है

[2019] 1 एससीआर 886

पैरा 121

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.684

2021 .

अपीलीय के 14.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की अपील No.182 में विद्युत न्यायाधिकरण।

के साथ

2021

की सिविल अपील No.6927।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., गोपाल जैन, जी. उमापति, एम. जी.

रामचंद्रन, डॉ. ए. एम. सिंघवी, डेरियस खंबाटा, साजन पूवय्या, सिद्धार्थ दवे, एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेसर्स के लिए अनूप जैन, उदित गुप्ता। एम/एस के लिए उदित किशन एंड एसोसिएट्स, जी. साई कुमार, समीर मलिक, सुश्री एक्षा। डी. एस. के. लीगल, आनंद के. गणेशन, निकुंज दयाल, सुश्री पूर्वा सहगल, अमल नायर, शुभम आर्य, सुश्री कृति सोनी, सुश्री रितु अपूर्वा, सुश्री पल्लवी सहगल, सुश्री रितु अपूर्वा, रवि नायर, सुश्री शिखा सूद, सुश्री रीहा सिंह, सुश्री अनुमेहा स्मिटी, अनीश बजाज, नवीन प्रकाश, सुश्री अनुश्री वर्धन, सुश्री सृष्टि खिंदरिया, विश्व मुखर्जी, पुखरंभम [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रमेश कुमार, गिरिक भल्ला, यशश्री कांत, श्रीमती प्रियंका व्यास, महेश अग्रवाल, अमित कपूर, सुश्री गीतिका शर्मा, सुश्री पूनम सेनगुप्ता, सुश्री साक्षी कपूर, अविष्कार सिंघवी, अर्शित आनंद, सौनक राजगुरु, अमन शर्मा, सुश्री दीपसिका मिश्रा, अंकितेश ओझा, करण रुखाना, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री पल्लवी शर्मा, वैभव कालरा, निशांत कुमार, सुश्री अनीशा उपाध्याय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

सूचकांक *

परिचय।

आई.

पैरा 1 और 2

II.

नागरिक आवेदन में तथ्य NO.684 OF
2021

पैरा 3 से 29

III.

नागरिक आवेदन में तथ्य NO.6927 OF

30 से 39

2021

स्वयं के बारे में सुझाव

IV.

डिस्कॉम्स।

पैरा 43

वी.

स्वयं के बारे में सुझाव

सामान्य कंपनियाँ. पारस 44 और 45

V. संबंधित दस्तावेज।

.....

पारस 46 से 83

.

पारस 84 से 93

VI.

न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

VII. के संबंध में स्थिति प्रावधान

विनियामक यंत्र. पैरा 94 से 104

VIII. धारणाएँ।

पैरा 105

आगे

संक्षिप्त नामों की सूची:

वार्षिक अनुबंधित मात्रा

1 .

एसीक्यू

2 .

एपीएमएल

अडानी पावर महाराष्ट्र

सीमित

के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

3 .

एपीटीईएल

नियंत्रक और लेखा परीक्षक

सी एंड एजी

4 .

भारत के जनरल

* एड नोट: सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

एच. टी. आर. ए. राज्य विद्युत वितरण कंपनी एन. आई. पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई,
सीसीईए

मंत्रिमंडल समिति

आर्थिक मामले

केंद्रीय विद्युत नियामक

सीईआरसी

आयोग

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल

कैप्टिव पावर प्लांट

सीपीपी

वितरण कंपनियाँ

डिस्कॉम

ईंधन आपूर्ति समझौता

एफएसए

जीसीवी

सकल कैलोरी मूल्य

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड

जीएमआर

जी. एम. आर. एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड

जीएमआरईटीएल

स्वतंत्र बिजली उत्पादन

आईपीपी

एलओए

आश्वासन पत्र

महाराष्ट्र बिजली

एमईआरसी

कोयला मंत्रालय

एमओसी

विद्युत मंत्रालय

एमओपी

एमएसईडीसीएल

महाराष्ट्र राज्य विद्युत

1

वितरण कंपनी लिम

एनसीडीपी

नया कोयला वितरण पी

पीएलएफ

पादप भार कारक

बिजली खरीद एग्रीम

पीपीएस

बिजली बिक्री समझौता

पीएसए

आरएफपी

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

दक्षिण पूर्वी कोयला सीमा

एसईसीएल

एसएचआर

स्टेशन गर्मी दर

टीपीपीएस

ताप विद्युत केंद्र

यूएचबीवीएनएल

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण

वेस्टर्न कोल लिमिटेड

निगम लिमिटेड

सीएल [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिचय

1. कई अन्य अपीलों की तरह इन दोनों अपीलों में शामिल प्रश्न सामान्य हैं।

2. वर्तमान अपीलों में शामिल तीन मुद्दे भी हैं:

इन दो अपीलों के साथ सूचीबद्ध अन्य अपीलों में शामिल थे। हालाँकि, अन्य अपीलों में कुछ अन्य सहायक और आनुषंगिक मुद्दे भी शामिल हैं। इस प्रकार, पक्षों के विद्वान वकील के अनुरोध पर, हमने वर्तमान अपीलों को सुना है। हमने यह भी सुना है कि

विद्वान वकील तीन सामान्य प्रश्नों पर अन्य अपीलों में उपस्थित होते हैं।

नागरिक आवेदन संख्या में तथ्य। 684 2021 का

3. संक्षेप में, तथ्य जो 2021 की सिविल अपील No.684 में सामने आते हैं

ये इस प्रकार हैं:

4. अपीलकर्ता-महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "एमएसईडीसीएल" के रूप में संदर्भित) ने अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (इसके बाद "एपीएमएल" के रूप में संदर्भित) के साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (संक्षेप में "पीपीए") किए हैं। पीपीए में से पहला 8 सितंबर 2008 को 1320 मेगावाट ("1320 मेगावाट पीपीए") के लिए है; दूसरा 31 मार्च 2010 को 1200 मेगावाट ("1200 मेगावाट पीपीए") के लिए है; तीसरा 9 अगस्त 2010 को 125 मेगावाट ("125 मेगावाट पीपीए") के लिए है; और चौथा 16 फरवरी 2013 को 440 मेगावाट ("440 मेगावाट पीपीए") के लिए है। ये पी. पी. ए. प्रतिस्पर्धी बोली के अनुसरण में किए गए थे।

धारा 63 के तहत अपीलार्थी-एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा संचालित प्रक्रियाएँ विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद "विद्युत अधिनियम" के रूप में संदर्भित) को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक बोली दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाता है।

शक्ति (संक्षेप में "एमओपी")।

5. अपीलार्थी-एम. एस. ई. डी. सी. एल. और प्रत्यर्थी संख्या 1-ए. पी. एम. एल. सौदों के बीच 31 मार्च 2010 को 1200 मेगावाट के पी. पी. ए. का अनुच्छेद 10 पारित किया गया।

"कानून में परिवर्तन" के साथ।

6. अनुच्छेद 10.1। 2 "कानून में परिवर्तन" शब्द को परिभाषित करता है।

7. अनुच्छेद 10.2 के लिए अनुप्रयोग और सिद्धांतों से संबंधित है

कानून में परिवर्तन के प्रभाव की गणना करना। अनुच्छेद 10.2। 1 यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 10 के तहत कानून में परिवर्तन के परिणाम का निर्धारण करते समय, उस सिद्धांत को उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन वितरण कंपनी को क्षतिपूर्ति करता है।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

नीति, 2007 (इसके बाद "एन. सी. डी. पी., 2007" के रूप में संदर्भित)। एन. सी. डी. पी. 2007 के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में "सी. आई. एल".) द्वारा सी. आई. एल. द्वारा घोषित/अधिसूचित की जाने वाली निर्धारित कीमतों पर ईंधन आपूर्ति समझौते (संक्षेप में "एफ. एस. ए".) के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की मानक आवश्यकता के अनुसार मात्रा की 100% पर विचार किया जाना था। एन. सी. डी. पी., 2007 ने यह भी प्रावधान किया कि कोयले की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. यदि संभव हो तो समय-समय पर कोयले का आयात करना पड़ता है। सी. आई. एल. को अपने समग्र मूल्य को उसी के अनुसार समायोजित करना था। इसने आगे प्रावधान किया कि यह सी. आई. एल./कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी थी कि वे पूरी तरह से पूरा करें।

यदि आवश्यक हो तो आयात का सहारा लेकर भी एफ. एस. ए. के तहत कोयले की आवश्यकता।

10. यह विवाद में नहीं है कि एन. सी. डी. पी., 2007 के अनुसार, ए. पी. एम. एल. ने एम. ओ. सी. को कोयला जोड़ने के लिए आवेदन किया था। यह भी विवाद में नहीं है कि

वेस्टर्न कोल लिमिटेड ("डब्ल्यू. सी. एल".) और साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड ("एस. ई. सी. एल".) ने ए. पी. एम. एल. और कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति के पक्ष में दो आश्वासन पत्र (एल. ओ. ए.) जारी किए।

11. निर्विवाद रूप से, एफ. एस. ए. को ए. पी. एम. एल. और डब्ल्यू. सी. एल. के बीच निष्पादित किया गया था।

घरेलू कोयला लिंकेज के लिए। इसके बाद, एफ. एस. ए. में संशोधन किया गया और डब्ल्यू. सी. एल. द्वारा आश्वस्त कोयले की मात्रा एस. ई. सी. एल. को हस्तांतरित कर दी गई।

12. यह भी विवाद में नहीं है कि बाद में 21 जून 2013 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (संक्षेप में "सी. सी. ई. ए".) ने घरेलू कोयले की लगातार कमी को देखते हुए, बिजली उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति के लिए एक संशोधित तंत्र को मंजूरी दी गई।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. इसके बाद, भारत सरकार ने मंत्रालय के माध्यम से

कोयला, दिनांक 26 जुलाई 2013 को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन (इसके बाद "एन. सी. डी. पी. 2013" के रूप में संदर्भित), जिससे एक संशोधित व्यवस्था को मंजूरी मिली।

चिन्हित ताप विद्युत केन्द्रों (संक्षेप में "टी. पी. पी.") को कोयले की आपूर्ति के लिए। उक्त कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान किया गया है कि सामान्य कोयला संपर्क वाले बिजली संयंत्रों के लिए 12 वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और वार्षिक अनुबंधित मात्रा (संक्षिप्त में "एसीक्यू") के 75 प्रतिशत की घरेलू कोयले की मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसने आगे प्रावधान किया कि उक्त 78,000 मेगावाट टी. पी. पी. की आवश्यकता के प्रति शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. कोयले का आयात कर सकती है और लागत-प्लस आधार पर इच्छुक बिजली संयंत्रों को इसकी आपूर्ति कर सकती है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि बिजली संयंत्र सीधे कोयले का आयात भी कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं, तो आयात घटक की सीमा तक सीआईएल की ओर से एफएसए दायित्वों को माना जाएगा

छुट्टी दे दी।

14. 31 जुलाई 2013 को, एम. ओ. पी. ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ("सी. ई. आर. सी.") और राज्य को एक पत्र जारी किया।

विद्युत नियामक आयोग मामले-दर-मामले के आधार पर वैकल्पिक कोयले (घरेलू लिकेज कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए) की लागत को शुल्क में पारित करने के रूप में विचार करेंगे।

15. यह तर्क देते हुए कि कानून में बदलाव के कारण, ए. पी. एम. एल. सुआवजे का हकदार था, ए. पी. एम. एल. ने 17 दिसंबर 2013 को महाराष्ट्र बिजली विभाग के समक्ष 2013 का मामला संख्या 189 वाली याचिका दायर की।

विनियामक आयोग (संक्षेप में "एम. ई. आर. सी.")।

16. एम. ई. आर. सी. ने 15 जुलाई 2014 के आदेश के माध्यम से उक्त याचिका (यानी 2013 का मामला संख्या 189) का निपटारा करने के लिए एक रूपरेखा को मंजूरी दी।

21 जून 2013 के सी. सी. ई. ए. निर्णय और 31 जुलाई 2013 की एम. ओ. पी. की सलाह को देखते हुए प्रतिपूरक ईंधन शुल्क का निर्धारण।

17. 15 जुलाई 2014 के एम. ई. आर. सी. के आदेश के अनुपालन में, ए. पी. एम. एल. ने एम. ई. आर. सी. के समक्ष मामला संख्या 140 वाली एक और याचिका दायर की।

18. एम. ई. आर. सी. ने 20 अगस्त 2014 के अपने आदेश के माध्यम से प्रतिपूरक ईंधन के शुल्क में वृद्धि के लिए एक तंत्र तैयार किया। शुल्क जिसे 2013 के मामले No.189 में अनुमति दी गई थी।

19. इसके बाद, ए. पी. एम. एल. ने 2014 के एम. ई. आर. सी. केस No.159 के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की।

एम. ई. आर. सी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। लिमिटेड।
बी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

20. 28 जनवरी 2016 को एमओपी ने संशोधित शुल्क नीति जारी की। संशोधित शुल्क नीति के खंड 6.1 के अनुसार, उपयुक्त आयोग प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं के शुल्क में घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए आयातित/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत पर विचार करना आवश्यक था।

21. इसके बाद, 9 मार्च 2016 को, एपीएमएल ने इसके समक्ष अपील दायर की।

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "ए. पी. टी. ई. एल". के रूप में संदर्भित), अपील सं। 129 2013 के मामले Nos.189 और 2013 के मामले Nos.189 में एम. ई. आर. सी. द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए

2014. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने भी एम. ई. आर. सी. के आदेशों के खिलाफ अपील संख्या दायर की। 187 और 2016 का 188।

22. 4 मई 2017 को, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने मुद्दों को रिमांड पर ले लिया

ए. पी. एम. एल. और एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा दायर क्रॉस-अपील में उठाए गए नए मामले

एनर्जी वॉचडॉग बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में एम. ई. आर. सी. द्वारा विचार।
केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग और अन्य 1 जो 11 अप्रैल 2017 को तय किया गया था।

23. 7 मार्च 2018 के आदेश से एम. ई. आर. सी. ने मामले का फैसला किया

2013 का <आई. डी. 1 और 2014 का 140, जिसमें 1180 मेगावाट क्षमता के लिए कानून में बदलाव के कारण राहत के लिए ए. पी. एम. एल. के दावों को अनुमति देते हुए, इसने इसे निर्दिष्ट न्यूनतम आपूर्ति दायित्वों की सीमा तक सीमित कर दिया।

सी. आई. एल. की सहायक कंपनियों के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम चार वर्षों के लिए अर्थात् एन. सी. डी. पी., 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक। इसने आगे कहा कि घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक कोयले की मात्रा की गणना बोली दस्तावेजों में एपीएमएल द्वारा उल्लिखित स्टेशन हीट रेट ("एस. एच. आर".) और एफ. एस. ए./एल. ओ. ए./एम. ओ. यू. के अनुसार घरेलू कोयले के लिए सुनिश्चित कोयला ग्रेड के सकल कैलोरी मूल्य ("जी. सी. वी".) के मध्य मूल्य के आधार पर की जाएगी।

24. इससे व्यथित होने के कारण, ए. पी. एम. एल. ने अपीलों को प्राथमिकता दी

एपीटीईएल सीखा। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने निम्नलिखित तीन मुद्दों को तैयार किया:

" मुद्दा संख्या 1: क्या एम. ई. आर. सी. धारण करने में सही था

सहायक उपभोग में प्रस्तुत शुद्ध एसएचआर कि अपीलार्थी द्वारा अपनी बोली या एसएचआर और

नए उत्पादन स्टेशनों के लिए निर्दिष्ट मानदंड

1 (2017) 14 एससीसी 80 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. वाई. टी. विनियम, 2011 के तहत, जो भी बेहतर हो, उसके तहत कानूनी मुआवजे में परिवर्तन की गणना करने का आधार बनेगा।

पीपीएस?

क्या एम. ई. आर. सी. धारण करने में सही था

मुद्दा संख्या 2:

कि सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले का संदर्भ जी. सी. वी. एल. ओ. ए./एफ. एस. ए./में सुनिश्चित कोयला श्रेणी के जी. सी. वी. श्रेणी का मध्य मूल्य होगा।

एमओयू और जीसीवी नहीं जैसा कि प्राप्त हुआ?

क्या एम. ई. आर. सी. धारण करने में सही था

मुद्दा संख्या 3:

कि कानून में परिवर्तन के उद्देश्य से

1180 मेगावाट क्षमता के लिए मुआवजे, घरेलू लिंकेज कोयले में कमी का आकलन कोयले की आपूर्ति को अधिकतम (1) एलओए/एफएसए के तहत सीआईएल द्वारा उठाव के लिए प्रस्तावित कोयले की वास्तविक मात्रा और (2) संबंधित वर्ष के लिए एन. सी. डी. पी. 2013 में न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा के रूप में मानते हुए किया जाएगा।

25. अंक संख्या 1 पर, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने माना कि ए. पी. एम. एल.

एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियम 2011 में निर्दिष्ट एस. एच. आर. या ए. पी. एम. एल. द्वारा प्राप्त वास्तविक एस. एच. आर., जो भी कम हो, के आधार पर कानून में परिवर्तन के आधार पर मुआवजे का हकदार है।

26. अंक संख्या 2 पर, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अभिनिर्धारित किया कि क्षतिपूर्ति

एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित कानून में परिवर्तन की गणना प्राप्त कोयले के वास्तविक जी. सी. वी. के आधार पर की जाएगी।

27. अंक संख्या 3 पर, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा कि एन. सी. डी. पी. के तहत,

2007 , कोयले की आपूर्ति का आश्वासन था और इस तरह, कानून में बदलाव के आधार पर मुआवजा देते समय, 12 वीं योजना के संबंधित चार वर्षों के लिए इसे अधिकतम 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक सीमित करना उचित नहीं था।

28. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अभिनिर्धारित किया कि पुनर्स्थापन सिद्धांत को

लागू किया जाता है। इसने आगे कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, जनरेटरों ने स्वयं संकेत दिया था कि जो मापदंड अधिक हैं

उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक अर्थात् वास्तविक में निम्न या विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

29. इससे व्यथित होकर, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने इस बारे में संपर्क किया है

2021 की सिविल अपील No.684 के माध्यम से न्यायालय।

2021 के नागरिक आवेदन NO.6927 में तथ्य

30. 2021 की सिविल अपील No.6927 में, MSEDCL ने चुनौती दी है

सी. ई. आर. सी. द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2018 को पारित समवर्ती आदेश और 16 जुलाई 2021 को विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश।

31. एमएसईडीसीएल ने 15 मई को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया

2009 और खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की

दीर्घकालिक आधार पर शक्ति। जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड (संक्षेप में "जी. एम. आर.") ने 7 अगस्त 2009 को अपनी बोली प्रस्तुत की और 5 करोड़ रुपये के स्तरीय शुल्क के साथ सफल बोलीदाताओं में से एक के रूप में उभरा। 2.879 / kWh। तदनुसार, दीर्घावधि आधार पर एमएसईडीसीएल द्वारा 17 मार्च 2010 को 200 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए पीपीए निष्पादित किया गया था। इसी तरह मार्च 2012 में, उत्तरदाता संख्या 2-केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (संक्षेप में "डी. एन. एच.") ने बिजली की खरीद के लिए एक आर. एफ. पी. जारी किया।

प्रतिस्पर्धी बोली और जी. एम. आर. सफल बोलीदाताओं में से एक के रूप में उभरे।

32. नतीजतन, सिविल अपील में प्रतिवादी संख्या 1 No.6927

2021 अर्थात् जी. एम. आर. ने परियोजना से बिजली की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित दीर्घकालिक पी. पी. ए. किए:

(क) दिनांक 17 मार्च 2010 के पीपीए के संदर्भ में एमएसईडीसीएल को दीर्घकालिक आधार पर 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति और बिक्री। कट-ऑफ

इस पी. पी. ए. की तिथि 31 जुलाई 2009 है। बिजली की आपूर्ति के संदर्भ में

पी. पी. ए. 17 मार्च 2014 से शुरू हुआ।

(ख) दीर्घकालिक आधार पर 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति और बिक्री

बिजली विभाग, डी. एन. एच. दिनांक 21 मार्च को पी. पी. ए. के संदर्भ में

पी. पी. ए. के संदर्भ में शक्ति 1 अप्रैल 2013 से शुरू हुई।

(ग) एक के बाद एक व्यवस्थाओं के माध्यम से TANGEDCO को दीर्घकालिक आधार पर 150 मेगावाट बिजली की आपूर्ति और बिक्री निम्नानुसार है:

(i) जी. एम. आर. एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड (जी. एम. आर. ई. टी. एल.) और जी. एम. आर. के बीच दिनांक 1 मार्च 2013 को बिजली बिक्री समझौता (पी. एस. ए.), जिसके आधार पर टैंगेडको को एक बोली प्रस्तुत की गई थी;

(ii) जी. एम. आर. ई. टी. एल. के बीच 27 नवंबर 2013 का पी. पी. ए.

और जी. एम. आर. से बिजली की आपूर्ति के लिए टैंगेडको। इस पी. पी. ए. की कट-ऑफ तिथि 27 फरवरी 2013 है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) जी. एम. आर. और जी. एम. आर. के बीच दिनांक 3 मई 2014 का पी. पी. ए.

जी. एम. आर. ई. टी. एल. और टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. के बीच पी. पी. ए. के अनुसार जी. एम. आर. ई. टी. एल. नियम और शर्तों को दर्ज करता है। आपूर्ति. पी. पी. ए. के तहत सत्ता की शुरुआत 22 अक्टूबर 2015 को हुई थी।

33. याचिका संख्या 8/एम. पी./2014 जी. एम. आर. द्वारा दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था

एम. एस. ई. डी. सी. एल. और डी. एन. एच. पी. पी. ए. के तहत संचालन अवधि और निर्माण अवधि के दौरान कानून की घटनाओं में परिवर्तन के प्रभाव के कारण मुआवजा। आयोग ने 1 फरवरी 2017 के आदेश द्वारा कानून में बदलाव के आधार पर जी. एम. आर. के कुछ दावों की अनुमति दी थी। उक्त आदेश के अनुसार, इसने कुछ दावों को भी अस्वीकार कर दिया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर, जी. एम. आर. ने आयोग द्वारा अस्वीकृत मुआवजे के दावों के संबंध में विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष 2017 की अपील संख्या 111 दायर की। इसी तरह, डी. एन. एच. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 1 फरवरी 2017 के उक्त आदेश के खिलाफ अपील संख्या 290/2017 दायर की गई थी, जिसमें कुछ कानूनी घटनाओं में बदलाव के तहत जी. एम. आर. को दिए गए मुआवजे के दावों पर विवाद किया गया था।

34. उपरोक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान, जी. एम. आर. ने निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए याचिका (यानी याचिका No.88/एम. पी./2018) दायर की है:

" (क) पुष्टि करता है कि निम्नलिखित परिचालन मापदंड जो

याचिकाकर्ता को देय मुआवजे की गणना अनिवार्य है कानूनी घटनाओं में परिवर्तन के कारण, वास्तविक आधार पर विचार किया जाना चाहिए:

((ii) स्टेशन ताप दर

((iii) सकल ऊष्मीय मूल्य

(ख) इस बात की पुष्टि करें कि रेल चालान के अनुसार सभी घटकों पर कोयला परिवहन पर सेवा कर और स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाता है।

(ग) याचिका संख्या 8/एमपी/2014 में आयोग के आदेश दिनांक 1.2.2017 के आलोक में प्रतिवादी संख्या 1, एमएसईडीसीएल से याचिकाकर्ता को देय राशि जारी करना।

35. संबंधित वर्तमान अपीलों में शामिल दो मुद्दे

एस. एच. आर. और जी. सी. वी. पर भी सी. ई. आर. सी. के समक्ष विचार किया गया।

36. सीईआरसी ने पाया कि सीईआरसी मानदंड इसके लिए लागू होते हैं

अवधि 2009-14 और 2014-19 300 मेगावाट इकाइयों के लिए मानदंड प्रदान नहीं करते हैं। इसने आगे पाया कि सी. ई. आर. सी. मानदंड महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ऊपर और ऊपर गर्मी दर के लिए क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत के क्षरण कारक प्रदान करते हैं।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

डिजाइन ऊष्मा दर। यह पाया गया कि चूंकि डिजाइन गर्मी दर 2211 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे है, इसलिए सकल गर्मी दर क्रमशः 2355 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे और 2310 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे की अवधि के लिए काम करती है। इसने निर्देश दिया कि कानून में बदलाव के तहत मुआवजे के लिए कोयले की खपत की गणना के लिए 2009-14 अवधि के दौरान 2355 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे का SHR और 2014-19 अवधि के दौरान 2310 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे या वास्तविक SHR, जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा।

37. जहां तक जी. सी. वी. का संबंध है, सी. ई. आर. सी. ने पाया कि आयोग के 2014 के टैरिफ विनियमों में जी. सी. वी. का मापन किया गया है।

"जैसा प्राप्त हुआ" के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, यह पाया गया कि यह उचित होगा यदि "जैसा प्राप्त हुआ" के आधार पर जी. सी. वी. को कानून में परिवर्तन के लिए मुआवजे की गणना के लिए माना जाए।

38. सी. ई. आर. सी. द्वारा 15 तारीख को पारित आदेश से व्यथित होना

नवंबर 2018 में, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष 2019 की अपील No.342 को प्राथमिकता दी। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. को प्रस्तुत करने में योग्यता नहीं पाई और इस तरह, 16 जुलाई 2021 के निर्णय और आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

39. इससे व्यथित होकर, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने 2021 की सिविल अपील No.6927 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

40. अपीलार्थी की ओर से दलीलें-सिविल में एमएसईडीसीएल

2021 की अपील No.684 विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन द्वारा की गई थी, जबकि 2021 की सिविल अपील No.6927 में तर्क विद्वान वकील श्री जी. साई कुमार द्वारा दिए गए थे।

41. हमने कुछ राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एम. जी. रामचंद्रन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह को भी सुना है, जिनके मामलों पर इस फैसले से निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिसमें उपरोक्त तीन प्रश्न/मुद्दे समान हैं।

42. प्रतिवादी-ए. पी. एम. एल. के साथ-साथ प्रतिवादी जी. एम. आर., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से आगे बढ़े।

तर्कों को। उनके तर्कों को विद्वान वकील श्री विश्व मुखर्जी द्वारा पूरक किया गया था।

स्वयं के डिस्कॉम्स पर प्रस्तुतियाँ

43. वितरण कंपनियों की ओर से जो मुख्य तर्क दिए गए थे (जिसे इसके बाद "डिस्कॉम्स" कहा गया है) वे इस प्रकार हैं:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एस. एच. आर. और जी. सी. वी. मूल्य बोली दस्तावेज में घोषित किए जाते हैं और उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए एस. एच. आर. मूल्य के आधार पर लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं है जो कि टैरिफ विनियमों या वास्तविक में दिए गए एस. एच. आर. मूल्य से अलग है। यह उनका निवेदन है कि केस-1 प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के मामले में परिचालन मानकों यानी एसएचआर और जीसीवी की घोषणा बोली का अधिदेश था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इस तरह से विचलन

कानून में परिवर्तन की अनुमति है, यह बोली की बहुत पवित्रता को छीन लेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोली प्रक्रिया में गंभीर भागीदारी सुनिश्चित करने और बिजली की आपूर्ति की शुरुआत को समय पर पूरा करने के लिए, प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश 2005 स्वयं बोली लगाने वाले/उत्पादक/उत्पादन करने वाली कंपनियों को अनिवार्य करता है

एक 'दृढ़' ईंधन व्यवस्था होना। यह उनका निवेदन है कि बोलीदाता/जनरेटर के लिए पी. पी. ए. की पूरी अवधि के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ईंधन की 'मात्रा' घोषित करना अनिवार्य है। डिस्कॉम्स ने तर्क दिया कि बोली में घोषित एसएचआर और जीसीवी घटकों को लागू करके ही ईंधन की मात्रा का पता लगाया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. एफ. पी. ने स्वयं भाग लेने को अनिवार्य किया है

पी. पी. ए. की 25 वर्षों की पूरी अवधि के लिए बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक ईंधन की 'मात्रा' के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता/जनरेटर।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'मात्रा' का पता लगाने के लिए, यह था

बोलीदाता/जनरेटर के लिए एसएचआर और जीसीवी घोषित करके 'सहायक गणना' प्रदान करना भी आवश्यक है।

पी. पी. ए. की पूरी अवधि के लिए लागू मूल्य।

डिस्कॉम्स की ओर से यह तर्क है कि बोली लगाने वाले/उत्पादक को अपनी बोलियां जमा करते समय सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए बोलियां जमा करनी होती हैं।

जिसमें उतार-चढ़ाव, ईंधन/कोयले की उपलब्धता आदि से संबंधित जोखिम शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ईंधन की उपलब्धता या उस दर के संबंध में कोई बदलाव होता है जिस पर कोयले की खरीद के लिए बोली लगाने वाले/जनरेटर की आवश्यकता होती है, तो बोली लगाने वाला/एच. टी. आर. ए. राज्य विद्युत वितरण कंपनी।

लिमिटेड। वी. एनआई पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

डिस्कॉम्स के तर्क का जोर यह है कि धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली आधारित पी. पी. ए. बिजली अधिनियम, उद्धृत शुल्क पवित्र है और कानून में परिवर्तन के प्रभाव से निपटने वाले पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 के अलावा, पी. पी. ए. के तहत उच्च शुल्क या अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने के लिए प्रतिवादी/उत्पादक के लिए यह खुला नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा रखी गई निर्भरता पूरी तरह से गलत है।

इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. डी. पी. 2013 के प्रभाव के लिए राहत केवल एन. सी. डी. पी. 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों की सीमा तक ही स्वीकार्य है और इसकी अधिकता में नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2013 को कानून में किया गया परिवर्तन एन. सी. डी. पी. 2007 की तुलना में था जो पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13.1 में प्रदान की गई कट-ऑफ तिथि यानी बोली जमा करने की तारीख से 7 दिन पहले लागू था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षतिपूर्ति करने का उद्देश्य ही

कानून में परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाना है जैसे कि कानून में परिवर्तन नहीं हुआ था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैरा 5.2 के साथ पठित एन. सी. डी. पी. 2007 के पैरा 2.2 के अनुसार, सी. आई. एल. इस कमी को पूरा करने का हकदार था। कोयले के आयात द्वारा घरेलू कोयले की उपलब्धता। ऐसी स्थिति में, जनरेटरों को अधिक लागत का भुगतान करना पड़ता था

सी. आई. एल. को आयातित कोयला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोलियां प्रस्तुत करते समय, बोलीदाताओं/उत्पादकों ने इस स्थिति को जानते हुए डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं कि सीआईएल द्वारा आयातित कोयले की आपूर्ति की स्थिति में उन्हें उद्धृत शुल्क/उद्धृत ऊर्जा शुल्क के अलावा आयातित कोयले की उच्च लागत के लिए अलग से मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि यदि जनरेटर कम कीमत पर ईंधन/कोयले की खरीद कर सकता था, तो उसे जो लाभ हुआ होगा

खरीद में बचत उसके पास गई होगी। उसी सादृश्य पर, यदि जनरेटर को ईंधन प्राप्त करने की आवश्यकता है/[2023] 8 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वास्तव में, 31 जुलाई 2013 तक यानी जब एन. सी. डी. पी. 2013 को लागू किया गया था, तब तक अधिक कोयले की लागत के लिए शुल्क में वृद्धि की अनुमति देने के लिए उत्पादकों की ओर से कोई दावा नहीं किया गया है

आयातित कोयले की आपूर्ति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि एन. सी. डी. पी. 2013

यदि कानून में बदलाव नहीं लाया गया होता, तो पहले जैसी स्थिति बनी रहती। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने लगातार कहा है कि एक अभूतपूर्व

निवेश लागत में वृद्धि किसी आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी अनुबंध या मांग के तहत दायित्वों का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकती है।

इस तरह के प्रदर्शन के लिए उच्च मूल्य या मुआवजा।

यह डिस्कॉम्स का निवेदन है कि एन. सी. डी. पी. 2013 द्वारा लागू किए गए कानून में बदलाव के कारण लाभ को केवल उक्त नीति द्वारा प्रदान की गई कमी की सीमा तक ही सीमित किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि एन. सी. डी. पी. 2013 का इरादा कमी के लिए कानून में परिवर्तन/नीतिगत निर्णय के माध्यम से राहत प्रदान करना था, तो भी

निर्दिष्ट प्रतिशत से नीचे यानी वास्तविक आधार पर पूरी कमी के लिए, तब निर्दिष्ट करने में कोई तर्क नहीं था

एन. सी. डी. पी. 2013 में प्रतिशत।

डिस्कॉम्स द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्पादन करने वाली कंपनियों का यह तर्क कि शक्ति नीति 2017 एन. सी. डी. पी. 2013 की निरंतरता थी, गलत है। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि शक्ति नीति 2017 के (ए) के तहत पहला भाग एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. की पुरानी व्यवस्था से संबंधित है जो कि एन. सी. डी. पी. पहलू है। (बी) के तहत दूसरा भाग शक्ति नामक नई पारदर्शी कोयला आवंटन नीति से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, शक्ति और कोयले का आवंटन

इसके तहत केवल उन संस्थाओं को ही अनुमति थी जिनके पास एन. सी. डी. पी. 2007 या एन. सी. डी. पी. के तहत कोई एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. नहीं था।

2013. इस संबंध में रिलायंस को रखा गया है

जयपुर विद्युत वितारन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

निगम लिमिटेड और अन्य बनाम। अदानी पावर राजस्थान
अदानी के रूप में संदर्भित)

लिमिटेड और अन्य 2 (इसके बाद

राजस्थान मामला ")

ऑनलाइन एससी 697 एच. टी. आर. ए. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लिमिटेड। वी. एनआई पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [वी. आर. गवई, जे.]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा स्पष्ट रूप से गलत और विकृत रूप में लागू किया गया है।

तरीके से।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवश्यक कोयले की कुल मात्रा की गणना अमूर्त तरीके से नहीं की जानी है, बल्कि

जरूरी रूप से बिजली स्टेशन के एसएचआर पर आधारित। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. एच. आर. का कोयले की गुणवत्ता या कोयले के जी. सी. वी. से कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएचआर एक थर्मल पावर स्टेशन की बॉयलर और टरबाइन विशेषता है और इसलिए, इसकी गुणवत्ता और दक्षता का संकेत है।

मशीन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कम एसएचआर के साथ कोयले की आवश्यकता की मात्रा कम होती है और उच्च एसएचआर के साथ बढ़ती है।

क्योंकि यह कोयले से ऊष्मा ऊर्जा निकालने के लिए मशीनों की क्षमता और दक्षता से संबंधित है ताकि प्रति इकाई बिजली का उत्पादन किया जा सके।

पी. पी. ए. की अवधि में बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा की पहचान करने के लिए शर्त दी जाएगी। अपनी बोली जमा करते समय और ऊर्जा शुल्क का हवाला देते समय, बोलीदाता/जनरेटर को कोयले की आवश्यकता की मात्रा को ध्यान में रखना आवश्यक था, जो बदले में, बोलीदाता/जनरेटर द्वारा दिए जाने वाले एसएचआर और सहायक खपत मानकों पर आधारित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोयले की मात्रा के लिए कोयला आपूर्ति समझौते पर सीआईएल द्वारा केवल एस. एच. आर. और बोलीदाता/उत्पादक द्वारा प्रदान किए गए संचालन मानकों के आधार पर ऊपर निर्धारित मात्रा के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण 2017 की अपील संख्या 210 में 13 अप्रैल 2018 के अपने फैसले में उन्हीं पक्षों के बीच लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जनरेटर द्वारा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि बोली मान ली जाती है कि एसएचआर 2200 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है और वास्तविक एसएचआर 2300 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है, जब उद्धृत शुल्क 2200 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के एसएचआर पर आधारित है, तो कानून में परिवर्तन के प्रभाव के लिए, 2300 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के एसएचआर का उपयोग कानून में परिवर्तन के लिए मुआवजे की गणना के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुमति देने वाला विवादित निर्णय

वास्तविक एस. एच. आर. या शुल्क विनियमों में दिया गया एस. एच. आर., जो भी कम हो, यदि बरकरार रखा जाता है, तो धारा 63 शुल्क निर्धारण के दायरे को धारा 62 लागत और शुल्क निर्धारण में परिवर्तित करने के बराबर होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिस्पर्धी बोली आधारित पी. पी. ए. में इसकी अनुमति नहीं है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एम. ई. आर. सी. प्रशुल्क विनियम स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि प्रशुल्क विनियम धारा 63 प्रशुल्क निर्धारण पर लागू नहीं होंगे और यह विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा शासित है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नियम और शर्तों) के विनियमन 2 (2) (ए) का अवलोकन

टैरिफ की शर्तों) विनियम, 2019 से पता चलेगा कि वे केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और बिजली अधिनियम की धारा 63 के तहत आयोग द्वारा अपनाए गए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से टैरिफ का पता चलने पर लागू नहीं होते हैं।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब बोली की शर्तों के अनुसार बोली को एसएचआर माना जाता है, तो विद्वान एपीटीईएल ऐसा नहीं कर सकता है

इक्विटी के कथित आधार पर इसे नजरअंदाज करें और टैरिफ के तहत अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक एसएचआर के कम्प्यूटेशनल उद्देश्य के लिए एक वैकल्पिक पैरामीटर प्रदान करें।

नियम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप बोली स्वीकार किए जाने और अंतिम होने के बाद बोली के नियमों और शर्तों में बदलाव होगा।

एच. टी. आर. ए. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. एनआई पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [वी. आर. गवई, जे.]

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निष्कर्ष यह है कि जीसीवी गणना 'जैसा प्राप्त हुआ' के आधार पर की जानी है, यह भी है

स्पष्ट रूप से गलत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गणना की उक्त पद्धति पर भरोसा करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य कोयला कंपनी द्वारा बिल किए गए कोयला ग्रेड की तुलना में वास्तव में आपूर्ति किए गए कोयला ग्रेड में ग्रेड फिसलन और उस अवधि के दौरान कोयले के ऊष्मा मूल्य में सभी नुकसान की वसूली करना है जब कोयले को कोयला खदानों से वितरण किया जाता है और बिजली संयंत्र में ले जाया जाता है और बिजली संयंत्र स्थल पर उतार दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोयला कंपनी द्वारा हवा में सुखाने के आधार पर जी. सी. वी. का मूल्यांकन बोली लगाने से पहले भी अच्छी तरह से ज्ञात/मौजूद था और उत्पादकों को इसके बारे में बहुत जानकारी थी। तदनुसार, इसे पहले ही कुछ समय में शामिल किया जा चुका है

उत्पादकों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। इस प्रकार, यदि जी. सी. वी. की गणना की अनुमति 'जैसा प्राप्त हुआ' के आधार पर दी जाती है, तो जनरेटरों को दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी मामले में, यह

प्रस्तुत किया जाता है कि यदि जनरेटरों को कोयले के ग्रेड यानी जी. सी. वी. रेंज और मात्रा के संबंध में कोई समस्या थी,

तब यह जनरेटरों और संबंधित कोयला कंपनियों के बीच एक मुद्दा है, जिसे हल करने की आवश्यकता है

अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि एम. ओ. पी. का पत्र, जिसे कानून में बदलाव की घटना माना जाता है, 31 जुलाई 2013 का है, इसलिए विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. 1 अप्रैल 2013 से इसे लागू नहीं कर सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ मुआवजे का लाभ देने की अनुमति देगा। जहां तक अडानी राजस्थान मामले में इस न्यायालय के फैसले पर उत्पादक कंपनियों द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले में कोई एफ. एस. ए. नहीं था और राज्य

सरकार ने पूरे कोयले की आपूर्ति करने का बीड़ा उठाया था मात्रा।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(XXVI) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) v के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और एक अन्य भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।

चूंकि उक्त मामला मामला-2 के तहत था।

(xxvii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक जनरेटर की असमर्थता

कोयला कंपनियों से पर्याप्त राहत एक कारण नहीं हो सकता है

वितरण लाइसेंसधारियों/डिस्कॉम या उपभोक्ताओं से राहत का दावा करना। कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति करने में विफलता के कारण डिस्कॉम को दंडित नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त कोयला।

() 2021 की सिविल अपील में एक अतिरिक्त आधार यह उठाया गया है कि सी. ई. आर. सी. ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि विलंब भुगतान अधिभार के सिद्धांत की परिकल्पना अनुच्छेद 8.3 में की गई है। 5 और 8. 8.3 से

पी. पी. ए. परिवर्तन के तहत राहत के संबंध में एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा शेष राशि के भुगतान के लिए लागू होता है।
कानून में।

जेनरेटिंग के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ कंपनियाँ

44. इसके विपरीत, यह उत्पादन की ओर से प्रस्तुत किया जाता है

पैनियाँ निम्नानुसार हैं:

((i)

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. डी. पी. 2007 के तहत, 100% मानक

65 % , 67 % और 12 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए ए. सी. क्यू. का 75 प्रतिशत अर्थात वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष तक वर्ष 2016-17।

((ख)

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. डी. पी. को एक कानून माना गया है

विद्युत अधिनियम के उद्देश्य। इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि उत्पादन कंपनियां एन. सी. डी. पी. 2013 के संदर्भ में कोयले की कमी के लिए मुआवजे की हकदार हैं और इसका भुगतान वास्तविक रूप से किया जाना है, अर्थात् कमी की सीमा तक।

कोयले की आपूर्ति वास्तव में मौजूद है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।

(iii)

और के मामले में इस न्यायालय के फैसले द्वारा कवर किया जाता है

बी) 11 एस. सी. सी. 508 एच. टी. आर. ए. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. एनआई पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) और अडानी राजस्थान मामले में

(ऊपर)।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमओपी द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, केस-1 बोली के लिए, एसएचआर और जीसीवी बोली मानदंड नहीं हैं।

बोली में उल्लिखित एस. एच. आर. और जी. सी. वी. तकनीकी जानकारी का हिस्सा है और परिवर्तन की गणना के लिए प्रासंगिक नहीं है।

कानूनी क्षतिपूर्ति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वहाँ महत्वपूर्ण हैं

केस-1 और केस-2 बोली के बीच अंतर। पहला यह है कि केस-1 बोली में एस. एच. आर. और जी. सी. वी. बोली मापदंड नहीं हैं, जबकि केस-2 में एस. एच. आर. और जी. सी. वी. बोली मापदंड हैं।

दूसरा, केस-1 बोली में, ऊर्जा शुल्क की गणना नहीं की जाती है क्योंकि ऊर्जा शुल्क उद्धृत शुल्क का हिस्सा है, जबकि केस-2 बोली में, ऊर्जा शुल्क की गणना वित्तीय बोली में उद्धृत शुद्ध ताप दर के आधार पर की जाती है। तीसरा, केस-1 बोली में, पी. पी. ए. के पास उद्धृत शुद्ध गर्मी दर/एस. एच. आर. की कोई परिभाषा नहीं है, जबकि केस-2 बोली में, पी. पी. ए. उद्धृत शुद्ध गर्मी दर/एस. एच. आर. को परिभाषित करता है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि केस-1 बोली में ऊर्जा आवेश के सूत्र में एसएचआर और जीसीवी पर कोई विचार नहीं किया जाता है, जबकि केस-2 बोली में इन दोनों पर विचार किया जाता है।

पैरामीटर गणना ऊर्जा के लिए सूत्र प्रदान करते हैं

शुल्क लेते हैं।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के मामले में

वर्धा पावर बनाम। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और Ors.¹

अभिनिर्धारित किया कि यदि बोली में प्रस्तुत किए गए एसएचआर और जीसीवी हैं

कानून मुआवजे में परिवर्तन के लिए विचार किया जाता है, इसका परिणाम हो सकता है

अधिक या कम वसूली में और केवल 'वास्तविक' पर विचार किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्धा पावर (उपरोक्त) में उक्त फैसले को चुनौती नहीं दी गई है/इसके खिलाफ अपील नहीं की गई है

और इस प्रकार अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

इस न्यायालय द्वारा समर्थित। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एम. ई. आर. सी. ने 2017 के मामले No.123 (जे. एस. डब्ल्यू. बनाम. एमएसईडीसीएल)

एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मान लिया है कि वास्तविक या मानक पैरामीटर का निचला स्तर

सहायक उपभोग के लिए (एसएचआर जैसे एक परिचालन मापदंड) कानून में बदलाव के लिए विचार किया जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमएसईडीसीएल ने नहीं किया है

उक्त निर्णय को चुनौती दी, जिसने इस प्रकार अंतिमता प्राप्त कर ली है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएचआर की लगातार निगरानी की जा रही है और इसका वास्तविक मूल्य, जैसा कि ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है,

दावों के साथ एमएसईडीसीएल को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, गणना उद्देश्यों के लिए 'वास्तविक' का पता लगाया और सत्यापित किया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि समान रूप से, कोयले का जी. सी. वी. तीसरे पक्ष की नमूना एजेंसियों द्वारा प्रमाणित है। जी. सी. वी. प्रमाणपत्र है

प्रत्येक रेलवे रेक के लिए अलग से एम. एस. ई. डी. सी. एल. को प्रस्तुत किया गया,

दावे के साथ। कम्प्यूटेशनल उद्देश्यों के लिए 'जैसा प्राप्त हुआ' के आधार पर इस तरह के 'वास्तविक' का पता लगाया/सत्यापित किया जा सकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सीईआरसी के समक्ष कार्यवाही में कुछ डिस्कॉम्स ने तर्क दिया है कि वास्तविक डिजाइन का पता लगाने के बाद एसएचआर पर विचार किया जाएगा

समय-समय पर सी. ई. आर. सी. विनियमों के अनुसार ऊष्मा दर और सीमा। उन्होंने आगे यह रुख अपनाया है कि सहायक उपभोग पर सी. ई. आर. सी. विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वैकल्पिक कोयले का जी. सी. वी. तीसरे पक्ष की नमूना एजेंसी द्वारा प्रमाणित होगा, जिसके लिए आयोग को उचित दिशानिर्देश प्रदान करने चाहिए। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब डिस्कॉम यह तर्क देते हुए यू-टर्न ले रहे हैं कि एसएचआर बोली के मानकों पर आधारित होना चाहिए।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कानून में बदलाव की कोई घटना नहीं होती, यानी कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होती, तो उत्पादन करने वाली कंपनियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता। उद्धृत ऊर्जा आवेश पर आधारित है। ऐसी स्थिति में कोयले का एसएचआर और जीसीवी सामने नहीं आया होगा।

एच. टी. आर. ए. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. एनआई पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

हालांकि, जब कानून में बदलाव की घटना होती है, तो 'बहाली' का सिद्धांत लागू होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'पुनर्स्थापना' केवल इसके साथ हो सकती है

'वास्तविक' मापदंडों पर विचार करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञ

सी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. जैसे निकायों ने एस. एच. आर. और जी. सी. वी. को 'वास्तविक' आधार पर निर्धारित करने की अनुमति दी है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि तकनीकी जानकारी के हिस्से के रूप में बोली में इंगित एसएचआर बहाली के जनादेश के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह जनरेटर को उसी आर्थिक स्थिति में वापस नहीं ला सकता है अगर कानून में परिवर्तन की घटना नहीं हुई थी।

यह एन. सी. डी. पी. 2007 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, सी. आई. एल. द्वारा कोयले की मानक आवश्यकता की आपूर्ति की जानी थी। हालांकि, देश में कोयले की कमी के कारण, की जिम्मेदारी

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. ई. आर. सी. वैधानिक का एक संयुक्त पठन 20 मई 2013 की सलाह, 21 जून 2013 का सी. सी. ई. ए. निर्णय, 31 जुलाई 2013 का एम. ओ. पी. पत्र और एम. ओ. पी. द्वारा जारी टैरिफ नीति 2016 के खंड 6.1 से पता चलता है कि

वैकल्पिक स्रोतों से खरीदे गए कोयले में कमी की मात्रा की उच्च लागत की अनुमति दी जानी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) और अदानी राजस्थान मामले (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों द्वारा इस स्थिति को बरकरार रखा गया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह पास-श्रू कोयले की सुनिश्चित मात्रा में कमी के कारण प्रतिपूर्ति के माध्यम से है और इसे एन. सी. डी. पी. 2013 में निर्दिष्ट प्रतिशत/ट्रिगर स्तरों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनर्स्थापन का सिद्धांत

सी. आई. एल. से आपूर्ति में कटौती की सीमा तक पास-श्रू की आवश्यकता होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदानी राजस्थान मामले (ऊपर) के मामले में इस अदालत द्वारा इसके विपरीत एक तर्क को पहले ही खारिज कर दिया गया है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xviii) एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) और अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) के मामलों में इस अदालत के फैसलों के अलावा, उत्पादन कंपनियां भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करती हैं।

निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) और एक अन्य वी. अदानी पावर

सीमित और अन्य।

(xix) यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि की ओर से विवाद

पता चलता है कि अडानी राजस्थान मामला (ऊपर) नहीं होगा वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होना, क्योंकि कोई एफ. एस. ए. परिदृश्य नहीं था, तथ्यात्मक रूप से भी गलत है।

45. उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, प्रतिवादी

2021 की अपील No.6927 अर्थात जी. एम. आर., निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ हैं

बनाया गया।

(i)

जी. एम. आर. और के बीच निष्पादित पी. पी. ए. की वह अनुसूची 10 एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि स्तरित शुल्क होगा

सी. ई. आर. सी. नियमों के अनुसार।

(ख)

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मानक एसएचआर जैसा कि में उल्लिखित है

बोली की गणना यह मानते हुए की जाती है कि बिजली संयंत्र संयंत्र भार कारक (संक्षेप में "पीएलएफ") के 85 प्रतिशत पर काम कर रहा है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. एल. एफ. के विवेकाधिकार पर है

प्रोक्योरर-डिस्कॉम्स जब वे शक्ति की मात्रा तय करते हैं

बंद करना-लेना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. एच. आर. वास्तविक समय में काम करने वाला है।

(iii)

पैरामीटर जो समय-समय पर बदलता रहता है, और इसकी गणना कुल उत्पन्न बिजली का पता लगाकर की जाती है

ऊष्मा मूल्य (के. सी. ए. एल.) में खपत कोयले की मात्रा।

(iv) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कोयले का जी. सी. वी. वास्तव में साइट पर वितरित किया जाता है और बॉयलर को खिलाया जाता है जो वैगन से वैगन में भिन्न होता है। यह.

एक सजातीय मान नहीं हो सकता है।

(v)

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बोली में दिए गए विवरण के साथ एस. एच. आर. और जी. सी. वी. के संबंध में केवल यह दर्शाने के लिए कोयला संपर्क का संकेत था कि जी. एम. आर. के पास निरंतर आधार पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक साधन थे और वह एक गंभीर बोलीदाता था, और पात्रता की अपनी बैठक को और प्रदर्शित करने के लिए।

आर. एफ. पी. के तहत निर्धारित आवश्यकता।

9) 5 एस. सी. सी. 325 ए. आर. ए. एस. टी. ए. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लिमिटेड। बी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

(vi) यह प्रस्तुत किया जाता है कि सहायक दस्तावेज/जानकारी

सी. ई. आर. सी. मानदंडों के अनुसार, जो 2355 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।
एस. ई. डी. सी. एल. अब 2211 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. की डिजाइन सकल ताप दर पर जोर दे रहा है, जिसके लिए भी विचार नहीं किया गया था।

बोली के समय कोयले की मात्रा की गणना प्रस्तुत करना।

(vii) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2017 और 18 अक्टूबर 2017 की अधिसूचनाओं के माध्यम से जी. सी. वी. में नुकसान को 'प्राप्त आधार' से 'फायर आधार' तक की अनुमति दी है और इस तरह, इसका कोई कारण नहीं है कि जी. सी. वी. की गणना 'प्राप्त आधार' पर क्यों नहीं की जा सकती।
(viii) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. को जी. एम. आर. के मामले की ए. पी. एम. एल. और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के साथ तुलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि जी. एम. आर. के अधिकार क्षेत्र में आता है -

सी. ई. आर. सी., जबकि अन्य दो के अधिकार क्षेत्र में आते हैं

एम. ई. आर. सी.

(ix) जहां तक विलंब भुगतान शुल्कों का संबंध है, यह है -

प्रस्तुत किया कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने एकतरफा रूप से राशि की कटौती की थी, जो पी. पी. ए. के प्रावधानों के विपरीत है और इस तरह, सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. दोनों ने सही माना है कि जी. एम. आर. अनुच्छेद 8.3 के संदर्भ में विलंब भुगतान अधिभार का हकदार था। 5 . इस संबंध में रिलायंस को रखा गया है

महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड V.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और

अन्य और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण

निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. एन. बिजली उत्पादन

कंपनी प्राइवेट लिमिटेड "

संबंधित दस्तावेज़

46. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, यह प्रासंगिक होगा

अभिलेख पर रखे गए कुछ दस्तावेजों के लिए।

47. एमओपी ने प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश, 2005 को अधिसूचित किया

इसके बाद 19 जनवरी 2005 को "उक्त दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया गया। कहा कि दिशा-निर्देश बिजली की धारा 63 के तहत बनाए गए थे

) 4 एस. सी. सी. 657

53 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावना के निम्नलिखित भाग का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

आईडी दिशानिर्देश।

“ 1 .

प्रस्तावना

ये दिशा-निर्देश अधिनियम की धारा 63 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य

वे इस प्रकार हैं:

1. बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना

वितरण लाइसेंसधारी;

2. खरीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

प्रक्रियाएँ;

3. विभिन्न क्षेत्रों में सूचना विषमताओं को कम करने में सुविधा प्रदान करना।

बोली लगाने वाले;

4. प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा प्रदान करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना।

बिजली की खरीद में शर्तें;

5. मानकीकरण को बढ़ाना और अस्पष्टता को कम करना और इसलिए परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का समय;

6. बिजली की उपलब्धता और शुल्कों पर निश्चितता सुनिश्चित करते हुए आपूर्तिकर्ताओं को आंतरिक संचालन पर लचीलापन प्रदान करना।

खरीदार "।

48. उक्त दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2 अभिजात वर्ग के दायरे से संबंधित है। उक्त दिशा-निर्देशों का पैरा 2.2 इस प्रकार है:

" 2.2 . दिशानिर्देश निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बेस-लोड, पीक-लोड और मौसमी बिजली आवश्यकताओं की खरीद के लिए लागू होंगे:

जहाँ स्थान, प्रौद्योगिकी या ईंधन निर्दिष्ट नहीं है

((i)

खरीददार (मामला 1);

पनबिजली परियोजनाओं, भार केंद्र परियोजनाओं या अन्य के लिए

((ख)

विशिष्ट ईंधन आवंटन के साथ स्थान विशिष्ट परियोजनाएं जैसे कि उपलब्ध कैप्टिव खदानें, जिन्हें खरीददार टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया (मामला 2) के तहत स्थापित करने का इरादा रखता है।

हालाँकि, बेस लोड या पीक लोड या मौसमी लोड आवश्यकताओं की खरीद के लिए अलग से आर. एफ. पी. का उपयोग किया जाएगा। 49. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पैरा 2 दो प्रकारों को अलग करता है। , मामला-1 और मामला-2।

मामला-1 उस मामले से संबंधित है जहां महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

स्थान, प्रौद्योगिकी या ईंधन खरीदार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। मामला-2 पनबिजली परियोजनाओं, भार केंद्र परियोजनाओं या विशिष्ट ईंधन आवंटन के साथ अन्य स्थान विशिष्ट परियोजनाओं जैसे कैप्टिव खानों से संबंधित है।

उपलब्ध है, जिसे खरीददार शुल्क आधारित बोली के तहत स्थापित करने का इरादा रखता है प्रक्रिया।

50. उक्त दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 3 तैयारी से संबंधित है -

बोलियों को आमंत्रित करना। पैरा 3.2 का खंड (I) मामला-2 से संबंधित है, जबकि पैरा 3.2 का खंड (II) मामला-1 से संबंधित है। पैरा 3.2 के खंड (II) के उपखंड (i) में बोली लगाने वाले को स्थल की पहचान करने और भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता होती है। बोलीदाता को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत विचाराधीन भूमि के लिए जारी अधिसूचना की एक प्रति जमा करनी होती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के हिस्से को छोड़कर, बोलीदाता को उक्त भूमि के कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र का आवंटन/पट्टा/स्वामित्व/निहित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। उपखंड (ii) के तहत, बोली लगाने वाले को बिजली स्टेशन के लिए पर्यावरण मंजूरी जमा करनी होती है। उप के अंतर्गत

खंड (iii), बोलीदाता को बिजली स्टेशन के लिए भूमि के लिए, यदि लागू हो, वन मंजूरी की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। उपखंड (iv) सबसे महत्वपूर्ण है।

वर्तमान विवाद के समाधान के लिए, जो इस प्रकार है:

बोलियां आमंत्रित करने की तैयारी

" 3 .

3.1

3.2

(आई)

(II)

(i)

(ख)

.....

(iii)

(iv) ईंधन की व्यवस्था: (क) निम्नलिखित मामलों में बिजली स्टेशन के उस चरण से बिजली उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा के लिए ईंधन की व्यवस्था करनी होगी, जिससे पीपीए की अवधि के लिए मानक उपलब्धता पर बिजली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है।



घरेलू कोयले के मामले में, बोलीदाता के पास होगा कोयला ब्लॉक आवंटन या ईंधन लिंकेज [2023] 8 एस. सी. आर. के माध्यम से ईंधन समझौते के लिए ठोस व्यवस्था की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

घरेलू गैस के मामले में, बोलीदाता के पास होगा
के माध्यम से ईंधन के लिए दृढ़ व्यवस्था की गई
भारत सरकार के गैस आवंटन के अनुसार अवधि और मात्रा के लिए दीर्घकालिक
ईंधन आपूर्ति समझौता

नीति

ख) निम्नलिखित मामलों में कुल स्थापित बिजली स्टेशन से बिजली उत्पन्न करने के लिए
आवश्यक ईंधन की मात्रा के लिए ईंधन की व्यवस्था करनी होगी।
क्षमता।

आयातित कोयले के मामले में, बोलीदाता ने या तो उन खदानों का अधिग्रहण
किया होगा जिनके लिए प्रमाणित भंडार हैं।
आवश्यक कोयले की मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत या कम से कम ईंधन आपूर्ति समझौता होना चाहिए।

50 % कम से कम पाँच (5) वर्ष की अवधि या पी. पी. ए. की अवधि के
लिए आवश्यक कोयले की मात्रा,

जो भी कम हो।

आर. एल. एन. जी. के मामले में, बोलीदाता ने कम से कम पांच (5) वर्षों की
अवधि या पी. पी. ए. की अवधि, जो भी कम हो, के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा के कम से कम 50
प्रतिशत के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते के माध्यम से ईंधन के लिए दृढ़ व्यवस्था की होगी।

आयातित और घरेलू कोयले के मिश्रण का उपयोग किया जा सकता है, जिस स्थिति में
आयातित और घरेलू कोयले के मानदंडों को मिश्रण के अनुपात में अलग से पूरा किया जाएगा।

51. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि घरेलू कोयले के मामले में बोली लगाने वाला है -

कोयले के माध्यम से ईंधन के लिए मजबूत व्यवस्था करने के लिए

आवंटन या ईंधन संयोजन।

52. पैरा 3.2 के खंड (II) के उपखंड (iv) का खंड (बी) आयातित कोयले से संबंधित है, जिस स्थिति में
बोलीदाता ने या तो अधिग्रहण किया होगा।

कोयले की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा के लिए सिद्ध भंडार होना

एड या कम से कम 50 प्रतिशत के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता होगा

कम से कम पाँच वर्ष की अवधि या अवधि के लिए आवश्यक कोयले का टी. ए. पी. ए., जो भी कम हो।

53. उक्त दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 4 शुल्क संरचना से संबंधित है।

पैरा 4.2 को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"

4. प्रशुल्क संरचना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं। लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [वी. आर. गवई, जे.]

4.1

.....

4.2 . विशिष्ट ईंधन आवंटन (मामला 2) के साथ दीर्घकालिक खरीद के मामले में, खरीदार क्षमता के आधार पर बोलियां आमंत्रित करेगा।

आवेश और शुद्ध उद्धृत ऊष्मा दर। बिजली की आंतरिक बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए शुद्ध गर्मी दर पूर्व-बस होगी।

स्टेशन। ऊर्जा शुल्क निम्नलिखित के अनुसार देय होगा:

सूत्र:

ऊर्जा प्रभार = शुद्ध उद्धृत ऊष्मा दर X अनुसूचित

जनरेशन X मासिक भारित ईंधन की औसत कीमत /

ईंधन का मासिक औसत सकल कैलोरी मूल्य

इसे उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित करना होगा। कोयला/लिग्नाइट ईंधन के मामले में, द्वितीयक ईंधन तेल की लागत को क्षमता शुल्क में शामिल किया जाएगा।

54. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां तक मामला-2 का संबंध है, खरीददार को क्षमता शुल्क और शुद्ध के आधार पर बोलियां आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है।

उद्धृत ऊष्मा दर। विद्युत केंद्र की आंतरिक बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए शुद्ध ताप दर पूर्व-बस होना आवश्यक है। यह आगे

यह प्रावधान है कि यदि ईंधन की कीमत भारत सरकार, सरकार द्वारा अनुमोदित तंत्र या ईंधन नियामक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, तो उसे उपयुक्त नियामक द्वारा अनुमोदित करना होगा।

आयोग।

55. पैरा 4.4 में प्रावधान है कि क्षमता शुल्क का भुगतान वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि Rs./kwh में उद्धृत शुल्कों के अनुसार होगा और

मानक उपलब्धता तक सीमित। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि केस-1 और केस-2 के तहत थर्मल स्टेशनों के लिए मानक उपलब्धता अधिकतम 85 प्रतिशत होगी।

56. पैरा 4.7 वर्तमान विवाद के समाधान के लिए एक और महत्वपूर्ण खंड है, जो इस प्रकार है:

" 4.7 . खरीददार को बिजली बेचने के व्यवसाय से लागत या राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून में कोई बदलाव

पहले है।

उस तारीख को लागू कानून जो [2023] 8 एस. सी. आर. के लिए अंतिम तिथि से 7 दिन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. एफ. पी. बोली जमा करने को अलग से समायोजित किया जाएगा। कानून में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में,

उपयुक्त आयोग लागू होगा।

57. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आर. एफ. पी. बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लागू कानून के संबंध में खरीदार को बिजली बेचने के व्यवसाय से लागत या राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून में किसी भी बदलाव को अलग से समायोजित किया जाएगा। इसमें प्रावधान है कि कानून में किसी भी बदलाव के प्रभाव के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, उपयुक्त आयोग का निर्णय लागू होगा।

58. पैरा 4.12 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 4.12 उत्पादन केन्द्रों की ऊष्मा दर के क्षरण के लिए कोई समायोजन प्रदान नहीं किया जाएगा। शुद्ध ऊष्मा दर के आधार पर बोलियों के मामले में भी, बोलीदाता साइट की स्थितियों, लोडिंग स्थितियों, आवृत्ति भिन्नताओं आदि को ध्यान में रखेगा और अनुबंध की अवधि के लिए उद्धृत शुद्ध ऊष्मा दर पर किसी भी समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

59. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उत्पादन स्टेशनों की ऊष्मा दर के क्षरण के लिए कोई समायोजन प्रदान नहीं किया जाना है। बोलियों के मामले में भी

शुद्ध ऊष्मा दर के आधार पर, बोलीदाता साइट की स्थितियों, लोडिंग स्थितियों, आवृत्ति भिन्नताओं आदि को ध्यान में रखेगा और अनुबंध की अवधि के लिए उद्धृत शुद्ध ऊष्मा दर पर किसी भी समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

60. एन. सी. डी. पी. 2007 महत्वपूर्ण होगा। इसका खंड 2 स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई. पी. पी.)/कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सी. पी. पी.) और उर्वरक क्षेत्र सहित विद्युत उपयोगिताओं से संबंधित है। खंड 2.2 का पाठ इस प्रकार है:

" 2. विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण और मूल्य निर्धारण

क्षेत्र (ओं):

2.1 .

2.2 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों सहित बिजली उपयोगिताएँ

(आई. पी. पी.)/कैप्टिव पावर प्लांट (सी. पी. पी.) और उर्वरक क्षेत्र

100 % ईंधन के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की मानक आवश्यकता के अनुसार मात्रा पर विचार किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर आपूर्ति समझौता (एफ. एस. ए.) सी. आई. एल. द्वारा घोषित/अधिसूचित किया जाएगा। ऐसी इकाइयाँ/बिजली संयंत्र, जिन्हें अभी चालू किया

जाना है, लेकिन जिनकी कोयले की आवश्यकताओं का आकलन पहले ही किया जा चुका है और जिन्हें कोयला मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

लैंक/आश्वासन पत्र (एल. ओ. ए.) अनुमोदित और साथ ही भविष्य प्रतिबद्धताओं को भी तदनुसार शामिल किया जाएगा।

61. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एन. सी. डी. पी. 2007 का आश्वासन 100%

कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की मानक आवश्यकता के अनुसार मात्रा, सीआईएल द्वारा घोषित/अधिसूचित की जाने वाली निर्धारित कीमतों पर सीआईएल द्वारा एफएसए के माध्यम से। इसने आगे प्रावधान किया कि ऐसी इकाइयाँ/बिजली संयंत्र, जिन्हें अभी चालू किया जाना है, लेकिन जिनकी कोयले की आवश्यकताओं का आकलन पहले ही किया जा चुका है

और एम. ओ. सी. द्वारा स्वीकार किए गए और अनुमोदित लैंकेज/आश्वासन पत्र (एल. ओ. ए.) के साथ-साथ भविष्य की प्रतिबद्धताओं को भी इसके अनुसार शामिल किया जाएगा।

62. खंड 5 के निम्नलिखित भाग पर ध्यान देना भी प्रासंगिक होगा।

एन सी डी पी 2007।

नए उपभोक्ताओं के लिए नीति

" 5 .

5.1 .

घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

5.2 .

कोयले का, सी. आई. एल. को आवश्यक कोयले का आयात करना पड़ सकता है

समय-समय पर, यदि संभव हो। सी. आई. एल. अपने समग्र मूल्य को तदनुसार समायोजित कर सकती है।

इस प्रकार, यह सीआईएल/कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इसे पूरा करें

आयात का सहारा लेकर भी एफ. एस. ए. के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता,

यदि आवश्यक हो। "

63. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एन. सी. डी. पी. 2007 का खंड 5.2 प्रदान करता है

कि कोयले की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि संभव हो तो सीआईएल को समय-समय पर कोयले का आयात करना पड़ सकता है। यह आगे बशर्ते कि सी. आई. एल. अपने समग्र मूल्य को तदनुसार समायोजित करेगी। एन. सी. डी. पी. 2007 सी. आई. एल./कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी पर जोर देता है कि यदि आवश्यक हो तो आयात का सहारा लेकर भी एफ. एस. ए. के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा किया जाए।

64. यह संबोधित संचार को संदर्भित करने के लिए भी प्रासंगिक होगा

सचिव, सी. ई. आर. सी. को दिनांक 9 मई 2013 के एमओपी द्वारा।

" विषय: घरेलू कारण से संपन्न पी. पी. ए. पर शुल्क पर प्रभाव
कोयले की उपलब्धता।

साहब,

विजली परियोजनाओं के लिए कोयला संपर्क प्रदान किए गए हैं

नई कोयला वितरण नीति 2007 (एन. सी. डी. पी.), जो अनिवार्य है
कि सी. आई. एल. विजली क्षेत्र की मानक आवश्यकता की 100% को पूरा करेगी।

एन. सी. डी. पी. के पैरा 5.2 में कहा गया है कि "घरेलू [2023] 8 एस. सी. आर. को पूरा
करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोयले की आवश्यकता होने पर, यदि संभव हो तो सीआईएल को समय-समय पर कोयले का आयात करना पड़ सकता है। सी. आई. एल. अपने समग्र मूल्य को तदनुसार समायोजित कर सकती है। इस प्रकार यह सी. आई. एल. की जिम्मेदारी होगी।

यदि आवश्यक हो तो आयात का सहारा लेकर भी कोयला कंपनियां एफ. एस. ए. के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करेंगी। एन. सी. डी. पी. के बाद एम. ओ. सी. ने इस धारणा के साथ 2008-2010 के बीच संबंध प्रदान किए कि यह लगभग 85 प्रतिशत पी. एल. एफ. पर कोयले की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा डेवलपर्स से बैंक गारंटी के रूप में प्रतिबद्धता गारंटी प्राप्त करने के बाद एल. ओ. ए. जारी किए गए थे, जिससे बिजली डेवलपर को निर्दिष्ट मात्रा तक कोयले की आपूर्ति करने का स्पष्ट दायित्व वहन किया गया था। एल. ओ. ए. प्राप्त करने के बाद विकासकर्ताओं ने तत्कालीन ईंधन आपूर्ति समझौते (एफ. एस. ए.) के तहत प्रचलित एल. ओ. ए. मात्रा के 90 प्रतिशत के विघटनकारी ट्रिगर के साथ घरेलू कोयले की आवश्यक मात्रा प्राप्त करने की धारणा पर आगे बढ़ना था, जिसमें सी. आई. एल. के लिए कोयले के आयात का सहारा लेने का प्रावधान था। ऐसा माना जाता है कि बिजली उत्पादकों ने इस आश्वासन को ध्यान में रखा होगा।

2. अब यह स्पष्ट हो गया है कि कोयला की सीमित उपलब्धता के कारण कर्नल मंत्रालय ने संकेत दिया है कि सीआईएल उन बिजली उत्पादकों को 60 से 65 प्रतिशत से अधिक एसीक्यू की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो सकता है जिन्हें पहले मानक मात्रा के एलओए जारी किए गए थे 85 प्रतिशत पीएलएफ के अनुरूप। इसके साथ ही यह प्रस्ताव किया गया है कि नए ईंधन आपूर्ति समझौतों में सीआईएल द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन को 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

इन बिजली उत्पादकों के साथ हस्ताक्षर किए जाने हैं। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां बिजली उत्पादकों को खुले बाजार से ईंधन की व्यवस्था करनी होगी जिसमें सीआईएल या उसके माध्यम से आयात भी शामिल होगा।

सीधे। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, पिछले कुछ वर्षों में घरेलू कोयले पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप डेवलपर्स और डिस्कॉम के बीच पहले से ही समझौते किए जा चुके हैं

लिकेज (एल. ओ. ए.) को उस अनुबंध को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए आयातित कोयले का उपयोग करना पड़ सकता है।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

दायित्व। बिजली उत्पादक संघ ने घरेलू कोयले की कमी और इसके परिणामी प्रभाव के इस मुद्दे पर प्रतिनिधित्व किया

प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से संपन्न पी. पी. ए. पर।

3. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. ई. ए.) ने कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार किया है, जिसके कारण सी. आई. एल. ने एल. ओ. ए. की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है। सी. सी. ई. ए. ने संयंत्रों के उत्पादन के संबंध में 06.02.2013 पर आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित दिशा-निर्देश तय किए हैं। 1.4.09 से 31.03.15 की अवधि के दौरान

कमीशन/कमीशन किया जाना:

सीआईएल सभी को लागत से अधिक के आधार पर आयातित कोयला उपलब्ध कराएगी

(i)

इस तरह की लागत लेने के लिए तैयार उत्पादक; कि आयातित कोयले की उच्च लागत की अनुमति दी जाएगी

(ख)

पार करें।

जिन्होंने इस तरह की प्रतिबद्धताओं और उपरोक्त पैरा में बताई गई परिस्थितियों के कारण बिजली डेवलपर्स द्वारा की गई बाजार ईंधन की खरीद की अतिरिक्त लागत को पारित करने की व्यवहार्यता के आधार पर वितरण कंपनियों के साथ पहले ही दीर्घकालिक पीपीए कर लिए हैं। सी. ई. आर. सी. से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह एस. ई. आर. सी./राज्य सरकारों को परामर्श जारी करने के लिए उचित तरीके सुझाए जो उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिए एम. ओ. पी. द्वारा जारी किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। 4. इस मामले में सी. ई. आर. सी. की सलाह का अनुरोध किया जाता है

जल्द से जल्द।

5. यह एम. ओ. एस. पी. (आई/सी) की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है। "

65. 9 मई 2013 के पत्र का अवलोकन स्पष्ट रूप से होगा।

कि एन. सी. डी. पी. 2007 आदेश देता है कि सी. आई. एल. 100% को पूरा करेगी

विद्युत क्षेत्र की अत्यधिक आवश्यकता। इसमें कहा गया है कि, एन. सी. डी. पी. 2007 के बाद, इस धारणा के साथ 2008-2010 के बीच संबंध प्रदान किया गया है कि यू. एल. डी. पी. एल. एफ. के लगभग 85 प्रतिशत पर कोयले की आवश्यकता को पूरा करता है। उस पर

, प्राप्त करने के बाद कोयला कंपनियों द्वारा एल. ओ. ए. जारी किए गए थे

[2023] 8 एस. सी. आर. से बैंक गारंटी के रूप में निटमेंट गारंटी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि कोई अंतर है तो उसे पाटें। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बिजली उत्पादकों ने कोयले की आपूर्ति के संबंध में इस आश्वासन को ध्यान में रखा होगा, जबकि दीर्घकालिक पी. पी. ए. के लिए केस-1 और केस-2 प्रतिस्पर्धी बोली के जवाब में अपनी बोलियां प्रस्तुत करना।

66. उक्त पत्राचार में आगे लिखा गया है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण, एम. ओ. सी. ने संकेत दिया है कि सी. आई. एल. उन बिजली उत्पादकों को 60 से 65 प्रतिशत से अधिक ए. सी. क्यू. की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो सकती है जिन्हें पहले पी. एल. एफ. के 85 प्रतिशत के अनुरूप मानक मात्रा के एल. ओ. ए. जारी किए गए थे। यह प्रस्ताव किया गया था कि इन बिजली उत्पादकों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले नए एफ. एस. ए. में सी. आई. एल. द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन को 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि इस परिदृश्य को देखते हुए, पी. पी. ए. जो पिछले कुछ वर्षों में घरेलू आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप डेवलपर्स और डिस्कॉम्स के बीच पहले ही संपन्न हो चुके हैं।

कोयला लिंकेज (एल. ओ. ए.) को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए आयातित कोयले का उपयोग करना पड़ सकता है।

67. संचार में आगे लिखा गया है कि सी. सी. ई. ए. ने कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार किया है, जिसके कारण सी. आई. एल. की ओर से अपनी एल. ओ. ए. प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए सी. सी. ई. ए. ने 6 फरवरी 2013 को आयोजित अपनी बैठक में संयंत्रों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश तय किए हैं।

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान कमीशन/कमीशन किया जाना:

(ख)

वह सीआईएल सभी को लागत से अधिक के आधार पर आयातित कोयला प्रदान करेगी

इस तरह की लागत लेने के लिए तैयार उत्पादक;

कि आयातित कोयले की उच्च लागत की अनुमति दी जाएगी

iii)

पार करें।

68. इसलिए इस पत्र में सीईआरसी से ईंधन की उपलब्धता के मुद्दे पर सरकार को सलाह देने का अनुरोध किया गया है

सी. आई. एल. की अपनी एल. ओ. ए. प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को दूर किया जा सकता है। सी. ई. आर. सी. से उचित महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी का सुझाव देने का भी अनुरोध किया गया था।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

जो उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है। 69. 9 मई 2013 के उपरोक्त संचार के अनुसरण में, सी. ई. आर. सी. ने घरेलू कोयले की उपलब्धता के कारण संपन्न पी. पी. ए. एस. के शुल्क पर प्रभाव के संबंध में बिजली अधिनियम की धारा 79 (2) के तहत 20 मई 2013 को सांविधिक सलाह जारी की। उक्त वैधानिक सलाह के निम्नलिखित भाग को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

" 2. आयोग में इस मामले पर विचार किया गया। आयोग देश में बिजली संयंत्रों से इष्टतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता की सलाह देता है। पर्याप्त मात्रा में कोयले की अनुपलब्धता ने बिजली उत्पादन के लिए गंभीर चुनौती पेश की है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) द्वारा संकलित आंकड़ों में परिलक्षित होता है: देश भर में उत्पादन स्टेशनों का संयंत्र भार कारक (पी. एल. एफ.) अभाव के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

सीआईएल/कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति।

3. सी. आई. एल. द्वारा चालू या चालू की जाने वाली सभी बिजली परियोजनाओं को लागत के साथ आयातित कोयले की आपूर्ति करने का प्रस्ताव।

आई. डी. 1 से आई. डी. 2 की अवधि के दौरान और इस तरह के कोयले को लेने के इच्छुक लोगों को वर्तमान में एन. सी. डी. पी. में उचित बदलाव की आवश्यकता होगी।

यदि आवश्यक हो तो आयात का सहारा लेकर भी एफ. एस. ए. के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करना सी. आई. एल. की पूरी जिम्मेदारी है। इसके बाद, सी. आई. एल./इसकी सहायक कंपनियों और बिजली उत्पादकों के बीच एफ. एस. ए. को पूरक समझौतों के माध्यम से संशोधित करना होगा।

70. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सी. ई. आर. सी. ने नोट किया है कि पर्याप्त मात्रा में कोयले की अनुपलब्धता ने बिजली उत्पादन के लिए गंभीर चुनौती पेश की है जैसा कि केंद्र द्वारा संकलित आंकड़ों में परिलक्षित होता है।

विद्युत प्राधिकरण (सीईए)। इसने आगे उल्लेख किया कि देश भर में उत्पादन स्टेशनों का पीएलएफ अभाव के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

सीआईएल/कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति। इसमें आगे लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान चालू या चालू होने वाली सभी बिजली परियोजनाओं के लिए लागत और लागत के आधार पर सी. आई. एल. द्वारा आयातित कोयले की आपूर्ति करने के प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए और इस तरह का कोयला लेने के लिए, एन. सी. डी. पी. में उचित बदलाव की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान में यह सी. आई. एल. की पूरी जिम्मेदारी है कि वह एफ. एस. ए. के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करे, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो आयात का सहारा लेकर भी। इसमें आगे कहा गया है कि सी. आई. एल./इसकी सहायक कंपनियों और [2023] 8 एस. सी. आर. के बीच एफ. एस. ए.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विजली उत्पादकों को पूरक समझौतों के माध्यम से संशोधित करना होगा। 71. खंड 10 का उल्लेख करने के बाद। 1 मामला-1 बोली प्रक्रिया के तहत शक्ति की खरीद के लिए मानक पी. पी. ए., जो 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है, की वैधानिक सलाह इस प्रकार बताती है:

" कानून में बदलाव के तहत किसी भी लाभ का दावा करने के लिए, परियोजना विकासकर्ता को उपयुक्त आयोग का रख करना होगा और इस संबंध में उस आयोग का निर्णय अनुच्छेद 10.3 के प्रावधानों के संदर्भ में अंतिम होगा। 3 और 10.3। 4 मानक पीपीए। उपयुक्त आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्णय लें, जिसमें आयातित कोयले के मुआवजे के लिए परियोजना विकासकर्ताओं के दावे भी शामिल हैं।

हितधारकों के साथ परामर्श "

72. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सी. ई. आर. सी. का कहना है कि कानून में बदलाव के तहत किसी भी लाभ का दावा करने के लिए, परियोजना विकासकर्ता को करना होगा उपयुक्त आयोग को भेजें। यह आगे दर्ज करता है कि उपयुक्त आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे हितधारकों के साथ परामर्श के बाद आयातित कोयले के कारण मुआवजे के लिए परियोजना डेवलपर्स के दावों सहित प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्णय लें।

73. उपरोक्त संचार के बाद, एम. ओ. सी. ने 21 जून 2013 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। यह संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा

उक्त प्रेस विज्ञप्ति के भाग के बाद।

" आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. ई. ए.) आज

बिजली को कोयले की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित तंत्र को मंजूरी दी गई

निर्माता:

टेपरिंग के मामलों सहित 78000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज, जिसे 31.03.2015 द्वारा चालू किए जाने की संभावना है। हालांकि वास्तविक कोयले की आपूर्ति तब शुरू होगी जब दीर्घकालिक बिजली उपलब्ध होगी।

खरीद समझौते (पी. पी. ए.) जुड़े हुए हैं।

(ii) समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चालू चार वर्षों के लिए 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ए. सी. क्यू.) के 75 प्रतिशत की घरेलू कोयले की मात्रा के लिए एफ. एस. ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

12 पंचवर्षीय योजना।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

(iii) अपने शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. कोयले का आयात कर सकती है और लागत से अधिक के आधार पर इच्छुक ताप विद्युत संयंत्रों (टी. पी. एस.) को इसकी आपूर्ति कर सकती है। टी. पी. पी. स्वयं भी कोयले का आयात कर सकते हैं। एम. ओ. सी. उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

(iv) सी. ई. आर. सी. द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाएगा। एम. ओ. सी. उपयुक्त आदेश जारी करेगा नई कोयला वितरण नीति (एन. सी. डी. पी.) का पूरक। एमओपी

सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. को उचित परामर्श जारी करना, जिसमें शामिल हैं -

उपयुक्त आयोगों को मामले-दर-मामले के आधार पर आयातित कोयले की उच्च लागत का भुगतान करने का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए बोली दिशानिर्देशों में यदि कोई संशोधन किया गया है।

74. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के चालू/शेष चार वर्षों के लिए 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत एसीक्यू की घरेलू कोयले की मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने थे। यह आगे देखा जा सकता है कि सी. सी. ई. ए. ने यह भी निर्णय लिया है कि सी. आई. एल. अपने शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर सकती है और लागत से अधिक के आधार पर इच्छुक टी. पी. पी. को इसकी आपूर्ति कर सकती है। टी. पी. पी. को स्वयं कोयला आयात करने की भी अनुमति दी जा सकती है। इसने आगे प्रावधान किया कि सी. ई. आर. सी. द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाना था।

75. इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने एम. ओ. सी. के माध्यम से 26 जुलाई 2013 को कार्यालय जापन जारी किया। उक्त कार्यालय

जापन इस प्रकार है:

नई कोयला वितरण नीति-आगे के निर्देश

" उप:

उसके कार्यान्वयन के संबंध में।

नई कोयला वितरण नीति (एन. सी. डी. पी.) इस मंत्रालय के कार्यालय जापन सं. 23011 / 4 / 2007 - सीपीडी

दिनांक 18.10.2007, विभिन्न क्षेत्रों में कोयले के वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए। उक्त नीति के पैरा 2 के अनुसार, स्वतंत्र बिजली उत्पादक सहित बिजली उपयोगिताओं को सी. आई. एल. द्वारा घोषित/अधिसूचित की जाने वाली निर्धारित कीमतों पर कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौते (एफ. एस. ए.) के माध्यम से उनकी मानक

आवश्यकता के अनुसार 100 प्रतिशत आपूर्ति की जाती थी। पैरा 5 के अनुसार, घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सी. आई. एल.

यदि संभव हो तो समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार कोयले का आयात करना था और तदनुसार समग्र मूल्य समायोजित करें।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. सरकार ने अब एक संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है 78, 000 मेगावाट क्षमता के चिन्हित ताप विद्युत स्टेशनों (टी. पी. पी.) को कोयले की आपूर्ति या तो चालू की गई या चालू होने की संभावना 01.04.2009 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान। समग्र घरेलू उपलब्धता और इन टी. पी. पी. की संभावित वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एफ. एस. ए.

सामान्य कोयला संपर्क वाले बिजली संयंत्रों के लिए 12 वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत एसीक्यू की घरेलू कोयले की मात्रा के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। तोड़फोड़ के मामले

टेपरिंग लिंकेज पुलिस के अनुसार लिंकेज को कोयले की आपूर्ति मिलेगी। उक्त 78,000 मेगावाट टी. पी. पी. एस. की आवश्यकता के प्रति अपने शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. कोयले का आयात कर सकती है और लागत से अधिक के आधार पर इच्छुक बिजली संयंत्रों को इसकी आपूर्ति कर सकती है। बिजली संयंत्र भी सीधे कोयले का आयात कर सकते हैं, यदि वे ऐसा चाहते हैं, जिसमें

मामले में, आयात घटक की सीमा तक सी. आई. एल. की ओर से एफ. एस. ए. दायित्वों का निर्वहन किया गया माना जाएगा।

3. नई कोयला वितरण नीति का पैरा 2.2 और 5.2 जारी किया गया ओ. एम. सं. 23011/4/2007-सी. पी. डी. दिनांकित 18.10.2007 स्टैंड मॉडिफाइड

उपरोक्त सीमा तक।

4. उपरोक्त दिशानिर्देश सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस. सी. सी. एल.) से कोयले के वितरण पर भी लागू होंगे।

5. सी. आई. एल. और इसकी सहायक कंपनियों और एस. सी. सी. एल. को आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है

तदनुसार कार्रवाई करें। "

समय-समय पर आवश्यकता होती है, यदि संभव हो, और तदनुसार समग्र मूल्य को समायोजित करें। 77. एन. सी. डी. पी. 2013 के पैरा 2 में कहा गया है कि सरकार ने अब 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान 78,000 मेगावाट क्षमता के चिन्हित टी. पी. पी. को कोयले की आपूर्ति के लिए एक संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि समग्र घरेलू उपलब्धता और इन टी. पी. पी. की संभावित वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए एफ. एस. ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

सामान्य कोयला संपर्क वाले बिजली संयंत्रों के लिए 12 वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए घरेलू कोयले की मात्रा 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और एसीक्यू का 75 प्रतिशत। इसमें आगे कहा गया है कि उक्त 78,000 मेगावाट टी. पी. पी. की आवश्यकता के प्रति शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी. आई. एल. कोयले का आयात कर सकती है और लागत के साथ-साथ इच्छुक बिजली संयंत्रों को इसकी आपूर्ति कर सकती है। इसमें आगे कहा गया है कि बिजली संयंत्र सीधे कोयले का आयात भी कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं, तो आयात घटक की सीमा तक सीआईएल की ओर से एफएसए दायित्वों को माना जाएगा: छुट्टी दे दी गई।

78. इसके तुरंत बाद, 31 जुलाई 2013 को, एमओपी ने सचिव, सीईआरसी को एक पत्र लिखा। यह संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा

उक्त संचार का पैरा 2, जो इस प्रकार है:

" 2. इसमें सभी पहलुओं और सी. ई. आर. सी. की सलाह पर विचार करने के बाद

इस संबंध में सरकार ने जून, 2013 में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

समग्र घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और

(i)

शेष चार वर्षों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ए. सी. क्यू.) के 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की मात्रा में प्रोत्साहन के लिए घरेलू कोयला घटक के लिए वास्तविक आवश्यकताएं, एफ. एस. ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 12 वीं योजना।

अपने शेष एफ. एस. ए. दायित्वों को पूरा करने के लिए, सीआईएल आयात कर सकती है

(ख)

कोयले की आपूर्ति करें और इच्छुक टी. पी. पी. को लागत से अधिक के आधार पर इसकी आपूर्ति करें। यदि वे चाहें तो टी. पी. पी. स्वयं भी कोयले का आयात कर सकते हैं।

आयातित कोयले की अधिक लागत पर विचार किया जाएगा

iii)

सी. ई. आर. सी. द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार "

79. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सरकार ने

इस संबंध में सभी पहलुओं और सी. ई. आर. सी. की सलाह पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया

कि सी. ई. आर. सी. द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाना था।

80. उक्त अनुच्छेद 4 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

संचार, जो इस प्रकार है:

" 4. सरकार के निर्णय के अनुसार, सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर आयात/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. और सी. आई. एल. [2023] 8 एस. सी. आर. में दर्शाई गई मात्रा में कमी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घरेलू कोयले की आपूर्ति जो 12 वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए शुल्क आधारित पहले से ही संपन्न पी. पी. ए. के लिए एल. ओ. ए. का न्यूनतम 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत होगी प्रतिस्पर्धी बोली "।

81. पैरा 4 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आयात/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की उच्च लागत को सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर पारित करने के लिए विचार किया जाना था।

एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. में इंगित मात्रा में कमी। यह आगे दोहराता है कि सी. आई. एल. घरेलू कोयले की आपूर्ति कर सकती है जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर पहले से ही संपन्न पी. पी. ए. के लिए 12 वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए एल. ओ. ए. का न्यूनतम 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत होगा।

82. इसके बाद एम. ओ. पी. ने 28 जनवरी 2016 के प्रस्ताव के माध्यम से

'शुल्क नीति' को अधिसूचित किया। उक्त नीति के खंड 6.1 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 6.0 जनरेशन

6.1 बिजली की खरीद

जैसा कि पैरा 5.1 में निर्धारित किया गया है, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बिजली की खरीद केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उपयोग करते हुए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र के माध्यम से होनी चाहिए। ये दिशा-निर्देश खरीद के लिए प्रदान करते हैं -

बेस लोड आवश्यकताओं और पीक लोड आवश्यकताओं के लिए अलग से बिजली। इससे विशेष रूप से ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता स्थापित करने में सुविधा होगी। हालांकि, 19 जनवरी, 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं को कोल इंडिया लिमिटेड से आवश्यक मात्रा में कोयला प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है

(सीआईएल)। सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले की कम मात्रा के मामले में, आश्वासन पत्र/एफ. एस. ए. में दर्शाई गई सुनिश्चित मात्रा या मात्रा की तुलना में, कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए आयातित/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत को किसी मामले में उपयुक्त आयोग द्वारा पारित करने के लिए माना जाएगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के अनुसार मामले के आधार पर ओ. एम. नं. एफ. यू.-12/2011-आई. पी. सी. (वोई-आई. जे. आई.) दिनांक 31.7.2013 "। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

83. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 28 जनवरी 2016 की शुल्क नीति में यह प्रावधान किया गया है कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बिजली की खरीद दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र के माध्यम से

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है। यह बेस लोड आवश्यकताओं और पीक लोड आवश्यकताओं के लिए अलग से बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसमें आगे कहा गया है कि 19 जनवरी, 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं को सीआईएल से आवश्यक मात्रा में कोयला प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह आगे प्रदान करता है कि कम मात्रा के मामले में

सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले की तुलना में एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. में दर्शाई गई सुनिश्चित मात्रा या मात्रा की तुलना में, कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए आयातित/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत को उपयुक्त आयोग द्वारा मामले के आधार पर पारित करने के लिए माना जाएगा। यह विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांकित जारी परामर्श के अनुसरण में है।

31 सेंट जुलाई 2013।

न्यायाधीशों का चयन किया गया

84. इन दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, अब हम उन निर्णयों पर विचार करेंगे जिन पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया जाता है। 85. एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में, कई दौर की मुकदमेबाजी के बाद, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा कि बिजली का उत्पादन और बिक्री

अदानी पावर द्वारा जी. यू. वी. एन. एल. और हरियाणा यूटिलिटीज को दिया गया था।

विद्युत अधिनियम की धारा 79 (1) (बी) के अर्थ के भीतर योजना और इसलिए, सी. ई. आर. सी. के पास मामले में आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसने आगे कहा कि उक्त मामलों के तथ्यों पर बल प्रयोग किया गया था और उस पर सी. ई. आर. सी./आयोग के आदेश को उलट दिया गया था। इसने यह भी माना कि कानून के प्रावधानों में परिवर्तन इन पर लागू नहीं होता है -

विदेशी कानून और इसलिए, इंडोनेशियाई कानून में परिवर्तन प्रावधानों के दायरे में नहीं आए। जहाँ तक भारतीय कानून में परिवर्तन थे

संबंधित, इसने माना कि जिन सरकारी नीतियों पर भरोसा किया गया था, वे "कानून" का गठन नहीं करती थीं। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के उक्त निर्णय पर इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था। इस न्यायालय ने बल प्रयोग के आधार पर तर्क को खारिज करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" 42. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हताशा का सिद्धांत इन मामलों पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि पी. पी. ए. एस. का मूल आधार अपरिवर्तित है। कहीं भी पी. पी. ए. में यह नहीं कहा गया है कि कोयले की खरीद केवल इंडोनेशिया से एक विशेष मूल्य पर की जानी है। वास्तव में, समग्र रूप से पी. पी. ए. को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि देय मूल्य [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोयले की आपूर्ति पूरी तरह से उस व्यक्ति के लिए है जो

सहन करने के लिए बिजली संयंत्र। यह तथ्य कि ईंधन आपूर्ति समझौते को पी. पी. ए. के साथ जोड़ा जाना है, केवल यह इंगित करने के लिए है कि संयंत्र के काम करने के लिए कच्चा माल है और क्रम में है। यह स्पष्ट है कि कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि से छूट नहीं मिलेगी।

कंपनियों को अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने से बहुत अच्छे कारण से उत्पन्न करना कि जब उन्होंने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं, तो यह एक जोखिम था जिसे उन्होंने जानबूझकर लिया था। हमारा विचार है कि केवल यह तथ्य कि बोली गैर-बढ़ाने योग्य हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तरदाताओं को निराशा की याचिका उठाने से रोका गया है, यदि अन्यथा यह कानून में उपलब्ध है और उनके द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। लेकिन यह तथ्य कि उदाहरण के लिए, अडानी मामले में गैर-वृद्धिशील शुल्क का भुगतान किया गया है, एक ऐसा कारक है जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। केवल यह दिखाने के लिए कि शुल्क पर बिजली की आपूर्ति का जोखिम

इंगित किया गया उत्पादन कंपनी पर था।
किया कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है।

86. इसके बाद इस न्यायालय ने इस बात पर विचार

डब्ल्यू का अर्थ "सभी कानून" तक बढ़ाया जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दिशानिर्देशों के खंड 5,17 के साथ खंड विज्ञापन से पता चलेगा कि यह इंडोनेशियाई कानून में परिवर्तन का संकेत देगा, क्योंकि यह विदेशी है न कि भारतीय कानून।⁸⁷ एनर्जी बॉचडॉग (ऊपर) में, इस न्यायालय ने 31 जुलाई 2013 के एमओपी संचार पर भी विचार किया था, जिसकी प्रासंगिकता हम पहले ही ऊपर यहाँ पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। यह टी इस प्रकार देखा गया:

" 56. हालाँकि, जहाँ तक भारतीय कानून में परिवर्तन के लिए खंड 13 की प्रयोज्यता का संबंध है, उत्तरदाता दृढ़ आधार पर हैं। यह देखा जाएगा कि खंड 13.1 के तहत 1 अगर कोई बदलाव है

परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस, विक्रेता की चूक के अलावा, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बेचने के व्यवसाय की किसी भी लागत में कोई बदलाव होता है, तब उक्त विक्रेता खंड 13.1 के तहत शासित होगा। 1 . विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 21-6-2013 के प्रस्ताव को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पहले की कोयला वितरण नीति दिनांकित 18-3-2007 के पत्र में निहित थी इसे संशोधित किया गया है क्योंकि सरकार ने अब कोयले की आपूर्ति के लिए एक संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लिया गया है कि समग्र घरेलू उपलब्धता और बिजली परियोजनाओं की संभावित आवश्यकता को देखते हुए, बिजली परियोजनाएं केवल एक निश्चित महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की हकदार होंगी।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

जो पहले स्वीकार्य था उसका प्रतिशत। इस मामले में,

31-7-2013 ”

88. इसके बाद इस न्यायालय ने 28 जनवरी 2016 की शुल्क नीति का उल्लेख किया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है यहाँ ऊपर हमारे द्वारा। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 57. 31-7-2013 दिनांकित पत्र और संशोधित शुल्क नीति दोनों अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए जा रहे वैधानिक दस्तावेज हैं।

और कानून की शक्ति प्राप्त करें। यह स्पष्ट है कि जहां तक भारतीय कोयले की खरीद का संबंध है, इस हद तक कि

विक्रेता के लिए लागत निर्धारित की जाएगी और केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग द्वारा तय की गई तारीख से प्रभावी होगी। इस मामले में, हमारा विचार है कि हालांकि इंडोनेशियाई कानून में परिवर्तन पीपीए के साथ पढ़े गए दिशानिर्देशों के तहत कानून में परिवर्तन के रूप में योग्य नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय कानून में परिवर्तन होगा। करेंगे "।

89. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कानून में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में तर्क ए. सी. क्यू. के आधार पर दिए जा रहे हैं।

संबंधित है, वही विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

90. अदानी राजस्थान मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को भी इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। उक्त मामले में एक तर्क भी प्रस्तुत किया गया था जिसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की गई है कि कानून में परिवर्तन का दावा केवल 35 से 40 प्रतिशत तक ही सीमित हो सकता है। उक्त तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 50. श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने तर्क दिया कि एफएसए ईंधन की आवश्यकता के लगभग 61 प्रतिशत से संबंधित है। इस प्रकार, कानून के दावे में परिवर्तन 35 से 40 प्रतिशत तक सीमित हो सकता है। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बोली दोहरी बोली पर आधारित नहीं थी। ईंधन, लेकिन घरेलू कोयले पर मूल्यांकन किया गया था। ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि बोली का मूल्यांकन घरेलू आधार पर किया गया था; [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुल्क 60 के उपरोक्त अनुपात में निर्धारित किया जाना था: 40 आयातित कोयले और घरेलू कोयले का क्रमशः प्रतिशत। इसके अलावा, हम ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश से पाते हैं कि कानून के प्रावधान में बदलाव घरेलू आपूर्ति में कमी तक सीमित होगा।

जोड़ने वाला कोयला। 51. यह स्पष्ट किया गया कि ए. पी. आर. एल. घरेलू लिंकेज कोयले की आपूर्ति में कमी की सीमा तक कानून के प्रावधान में बदलाव के तहत राहत का हकदार होगा। इस प्रकार, हम उठाए गए समर्पण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हम एपीटीईएल के निष्कर्षों को उचित, उचित पाते हैं।

और असाधारण "।

91. उक्त मामले में भी (यानी अडानी राजस्थान मामले में), कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान उसी के समान था जो इसके लिए आता है।

वर्तमान मामले में अपमान। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 59. नीति में परिवर्तन और किसी भी सहमति, मंजूरी और परमिट प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों में परिवर्तन या ऐसे प्राप्त करने के लिए किसी भी नए नियम या शर्तों को शामिल करना।

सहमति, मंजूरी और परमिट भी शामिल हैं। द.

अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि विदेशी कानून में बदलाव के कारण लाभ मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, गलत तथ्यात्मक आधार पर आधारित है। विदेशी कानून में बदलाव के आधार पर राहत का दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वीकार को कानून में बदलाव पर निर्भर किया गया है। पी. पी. ए. घरेलू कानून पर आधारित था और घरेलू कानून में बदलाव हुआ। इस प्रकार, परिणाम होना चाहिए फॉलो करें। राजस्थान सरकार ने कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए 2008 में एपीआरएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे

या अन्य स्रोतों से कोयला। 60. हम वर्तमान मामले के साथ-साथ एनर्जी वॉचडॉग में भी समानता पाते हैं। तथ्यात्मक मैट्रिक्स वर्तमान मामले के समान था।

हम पाते हैं कि आर. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने दर्ज किया है तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष। हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल शामिल नहीं है। एनर्जी वॉचडॉग में यह माना गया था कि 2007 के एन. सी. डी. पी. में 26.7.2013 के निर्णय से कानून में बदलाव लाया गया था। यह अनुच्छेद 10.2 में प्रदान किया गया है। 1 क्षतिपूर्ति के लिए कानून में परिवर्तन कैसे लागू किया जाना है

प्रभाव "।

92. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मामले में

3 वी. एन. एल.) (ऊपर), इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

[ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [वी. आर. गवई, जे.]

" 13. इसलिए, समग्र रूप से अनुच्छेद 13 को पढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा होती है जो अनुच्छेद में निहित पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांतों के अधीन है।

छूट जो 6-4 दिनांकित प्रशासनिक आदेशों द्वारा दी गई थी 2015 और 16-2-2016। अतः वर्तमान मामला अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत आता है। 1 ((i)। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि मासिक शुल्क भुगतान में समायोजन उस तारीख से प्रभावी होता है जिस दिन

दी गई छूट को वापस ले लिया गया। इस मामले में, शुल्क में इस तरह के बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा उठाए जाने वाले मासिक चालान उचित रूप से बदले गए शुल्क को दर्शाते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता उस तारीख से अपने मासिक शुल्क भुगतान में समायोजन के हकदार थे जिस दिन छूट अधिसूचनाएं प्रभावी हुईं। इस मामले में, अनुच्छेद 13.2 में निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत इस सरल कारण से लागू होगा कि यह 4 5-2017 [अदानी पावर लिमिटेड v. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ई. आर. सी. 66] कि सी. ई. आर. सी. ने माना कि

उत्तरदाताओं को अतिरिक्त लागत का दावा करने का अधिकार था

डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2015 कानून में परिवर्तन। इस मामले में, यह कहना गलत होगा कि उत्तरदाता पी. पी. ए. के बाहर इक्विटी के कुछ सामान्य सिद्धांत पर इस प्रतिस्थापन राशि का दावा करेंगे। चूंकि यह स्पष्ट है कि वहन लागत की यह राशि केवल

पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 से संबंधित, हम अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

93. इस न्यायालय ने विशेष रूप से डिस्कोम्स के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह जनरेटर पी. पी. ए. के बाहर इक्विटी के कुछ सामान्य सिद्धांत पर पुनर्स्थापन राशि का दावा कर रहा था। इस न्यायालय ने माना कि लागत की राशि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 से संबंधित थी।

संबंधित सांविधानिक प्रावधान

विनियामक यंत्र

94. अब हम बिजली के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करेंगे।

95. विद्युत अधिनियम की धारा 70 विद्युत प्राधिकरण ("सी. ई. ए.") के गठन से संबंधित है। सी. ई. ए. में शामिल नहीं होंगे

14 से अधिक सदस्य (इसके अध्यक्ष सहित) जिनमें से 8 से अधिक पूर्णकालिक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा नियुक्त किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार। विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (5) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" (5) प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किससे की जाएगी

क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों के बीच जिनके पास है

इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान और पर्याप्त अनुभव और क्षमता,

अर्थशास्त्र या औद्योगिक मामले, और कम से कम एक सदस्य होगा

निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक से नियुक्त, अर्थात्:

(ए) उत्पादन स्टेशनों के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग;

(ख) पारेषण और आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग

बिजली;

(ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान;

(घ) व्यावहारिक अर्थशास्त्र, लेखांकन, वाणिज्य या वित्त।

बिजली का वितरण और उपयोग। केंद्र सरकार को किसी भी मामले पर सलाह देना या किसी भी मामले पर उस सरकार को सिफारिश करना भी आवश्यक है, यदि सी. ई. ए. की राय में, सिफारिश से उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी। बिजली का पारेषण, व्यापार, वितरण और उपयोग।

98. विद्युत अधिनियम की धारा 76 सी. ई. आर. सी. के गठन का प्रावधान करती है। सी. ई. आर. सी. पाँच सदस्यीय निकाय है जिसमें एक

अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य, और सी. ई. ए. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष।

लिमिटेड। बी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

पदेन सदस्य कौन होगा। 6 उच्च अधिकारियों वाली एक उच्च स्तरीय चयन समिति सी. ई. आर. सी. के सदस्यों का चयन करती है और एपीटीईएल सीखा।

99. विद्युत अधिनियम की धारा 77 सी. ई. आर. सी. के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रदान करती है। धारा 77 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि सीईआरसी के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, कानून, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव होगा या उनसे निपटने की क्षमता दिखाई जाएगी। इसके लिए आगे यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति

नियुक्त व्यक्ति के पास बिजली उत्पादन, पारेषण या वितरण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव होना चाहिए। नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास वित्त के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव होता है। विद्युत अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के लिए आवश्यक है कि दो व्यक्तियों के पास अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून या प्रबंधन के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव। धारा 77 की उप-धारा (1) के लिए परंतुक

विद्युत अधिनियम में प्रावधान है कि खंड (ग) के तहत एक ही श्रेणी के तहत एक से अधिक सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

100. विद्युत अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (2), जो एक गैर-बाध्यकारी खंड है, केंद्र सरकार को नियुक्त करने का अधिकार देती है।

अध्यक्ष के रूप में उन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति जो है, या है

उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है। हालांकि, ऐसी नियुक्ति प्रमुख के साथ परामर्श के अलावा नहीं की जा सकती है।

भारत का न्याय।

101. विद्युत अधिनियम की धारा 79 सी. ई. आर. सी. के कार्यों से संबंधित है। धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत सी. ई. आर. सी. के कार्यों में से एक केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित उत्पादक कंपनियों के शुल्क को विनियमित करना है। खंड (बी) से खंड (ए) में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के अलावा अन्य उत्पादन कंपनियों के शुल्क को विनियमित करने की आवश्यकता होती है, यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना में प्रवेश करती हैं या अन्यथा करती हैं।

102. इसी तरह, विद्युत अधिनियम की धारा 82 राज्य आयोग के गठन से संबंधित है। विद्युत अधिनियम की धारा 83

दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों के बीच एक समझौते द्वारा एक संयुक्त आयोग का गठन करने की अनुमति देता है। यह केंद्र सरकार को एक या अधिक [2023] 8 एस. सी. आर. के संबंध में एक संयुक्त आयोग का गठन करने की भी अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की एक या अधिक सरकारों धारा 84 के तहत, अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति

राज्य आयोग के पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है और उसने क्षमता दिखाई है। विद्युत अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (2) राज्य सरकार को उन व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं। हालाँकि, ऐसी नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और सी. ई. ए. के अध्यक्ष या सी. ई. आर. सी. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय चयन समिति राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। विद्युत अधिनियम की धारा 79 के अनुरूप, धारा 86 राज्य आयोग के कार्यों को परिभाषित करती है। विद्युत अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में राज्य आयोग से बिजली खरीद और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करने की आवश्यकता है।

वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के लिए समझौते राज्य।

103. विद्युत अधिनियम की धारा 110 अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करती है। विद्युत अधिनियम की धारा 111 में उक्त अधिनियम (धारा 127 को छोड़कर) के तहत किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का प्रावधान है। धारा 112 अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि इसमें एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होंगे। धारा 113 अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान करती है। केवल एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वह अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनने का हकदार है। अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित तीन श्रेणियों का प्रावधान किया गया है:

(i) एक व्यक्ति एक न्यायाधीश है, या रहा है, या होने के लिए योग्य है।

उच्च न्यायालय; या

((ख)

एक व्यक्ति कम से कम एक वर्ष से सचिव है या रहा है।
आर्थिक मामलों या मामलों या बुनियादी ढांचे से निपटने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग में;
ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUT CO.

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

या

((iii) एक व्यक्ति सक्षम और प्रतिष्ठित व्यक्ति है या रहा है, जिसे बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण और विनियमन या अर्थशास्त्र, वाणिज्य से संबंधित मामलों से निपटने में पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है।

कानून या प्रबंधन।

104. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सी. ई. ए., सी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।

सम्बंध

105. एस. एच. आर. और जी. सी. वी. से संबंधित मुद्दे हैं

सी. ई. आर. सी. ने 15 नवंबर 2018 को अपने आदेश में कहा कि

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य

रिचिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. 3. यह प्रासंगिक होगा। सी. ई. आर. सी. के 15 नवंबर के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा प्रस्तुत करें।

जो इस प्रकार है:

" 29. एसएचआर और जीसीवी के संबंध में प्रस्तुतियाँ दी गई हैं विचार किया। ए. पी. टी. ई. एल. ने अपील में अपने निर्णय दिनांक 12.9.2014 में

2013 का सं. 288 (मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड V)

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड ए. एन. आर.) ने फैसला सुनाया है कि क्षतिपूर्ति

कानून में परिवर्तन के तहत ऊर्जा शुल्क और तकनीकी मानकों से गणना किए गए कोयले की कीमत के साथ सहसंबद्ध नहीं किया जा सकता है। जैसे बोली में दी गई कोयले की ऊष्मा दर और सकल जीसीवी

कोयले की आवश्यकता स्थापित करने के लिए दस्तावेज। प्रासंगिक ए. पी. टी. ई. एल. के अवलोकन निम्नानुसार निकाले गए हैं:

बोली में उद्धृत ईंधन की वास्तविक भूमि मूल्य के अनुरूप वास्तविक ऊर्जा शुल्क के साथ मेल नहीं खा सकता है। विक्रेता ने अपनी बोली में कोयले की कीमत का भी उल्लेख नहीं किया है। इसलिए, कोयले पर उपकर/उत्पाद शुल्क में परिवर्तन के कारण कानून में बदलाव के कारण मुआवजे को वित्तीय बोली में उद्धृत ऊर्जा शुल्क से गणना की गई कोयले की कीमत और ऊष्मा दर से जोड़ना सही नहीं है और

आयन No.88/MP/2018 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोयले की स्थापना के उद्देश्य से बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में दिए गए कोयले का सकल कैलोरी मूल्य

आवश्यकताएँ। इस प्रकार गणना की गई कोयले की कीमत कोयले की वास्तविक कीमत के बराबर नहीं होगी और इसलिए, कोयले की ऐसी कीमत पर गणना किए गए कानून में परिवर्तन के लिए मुआवजा विक्रेता की आर्थिक स्थिति को उसी स्तर पर बहाल नहीं करेगा।

मानो कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है।

30. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, बोली दस्तावेज के अनुसार कोयले की ताप दर और जी. सी. वी. जैसे तकनीकी मानकों पर कानून में परिवर्तन के तहत राहत की गणना के उद्देश्य से कोयले की आवश्यकता तय करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, बोली मापदंडों पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी, एम. एस. ई. डी. सी. एल. की प्रस्तुतियाँ स्वीकार्य नहीं हैं। उत्तरदाता ने भी भरोसा किया है

जीसीवी के संबंध में एमईआरसी आदेश पर। जहां तक एस. एच. आर. का संबंध है, एम. ई. आर. सी. द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि बोली में प्रस्तुत शुद्ध एस. एच. आर. या

एम. वाई. टी. के अनुसार नए थर्मल स्टेशनों के लिए निर्दिष्ट एस. एच. आर. मानदंड

एमएसईडीसीएल। 31. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने 2355 किलो कैलोरी/किलोवाट के एसएचआर पर विचार किया है, जबकि प्रतिवादी एमएसईडीसीएल ने

आर. एफ. पी. में प्रस्तुत 2211 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. की डिजाइन ऊष्मा दर को माना जाता है। यह उल्लेख करना उचित है कि 2009-14 और 2014-19 अवधि के लिए लागू CERC मानदंड 300 मेगावाट इकाइयों के लिए मानदंड प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन डिजाइन गर्मी दर के ऊपर और ऊपर गर्मी दर के लिए क्रमशः 6.5% और 4.5% के क्षरण कारक प्रदान करते हैं। चूंकि डिजाइन ऊष्मा दर 2211 किलोकैलरी/किलोवाट घंटा है, सकल ऊष्मा दर 2009-14 और 2014-19 की अवधि के लिए क्रमशः 2355 किलोकैलरी/किलोवाट घंटा (2211×1.065) और 2310 किलोकैलरी/किलोवाट घंटा (2211×1.045) है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि 2009-14 अवधि के दौरान 2355 किलो कैलोरी/kWh का SHR और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दौरान 2310 किलो कैलोरी/kWh।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

2014-19 की अवधि या वास्तविक एस. एच. आर. जो भी कम हो, उस पर कानून में बदलाव के तहत मुआवजे के उद्देश्य से कोयले की खपत की गणना करने के लिए विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता और

प्रत्यर्थी एम. एस. ई. डी. सी. एल. को इन दावों के कारण सालाना सुलह करने का निर्देश दिया जाता है।

32. जी. सी. वी. के मामले में, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह जी. सी. वी. बेंड का मध्य मूल्य होना चाहिए जिसे 'बिल के रूप में' के आधार पर मापा जाने वाले जी. सी. वी. पर लागू किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले के ग्रेड फिसलने के कारण, जी. सी. वी. पर 'बिल के रूप में' विचार करना उचित नहीं होगा। आयोग के 2014 के प्रशुल्क विनियमों में जी. सी. वी. के मापन को 'जैसा प्राप्त हुआ' के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, यह उचित होगा यदि जी. सी. वी. की गणना के लिए 'जैसा प्राप्त हुआ' आधार पर विचार किया जाए।

कानून में परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति "।

106. सी. ई. आर. सी. ने मैसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में 2013 की अपील संख्या 288 में 12 सितंबर 2014 के विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के फैसले का उल्लेख किया है। रिलायंस

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. जिसमें विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने आयोजित किया है

कि कोयले पर उपकर/उत्पाद शुल्क में परिवर्तन के कारण कानून में परिवर्तन के कारण मुआवजे को वित्तीय बोली में उद्धृत ऊर्जा शुल्क से संगणित कोयले की कीमत से जोड़ना सही नहीं है और

कोयले की आवश्यकता को स्थापित करने के उद्देश्य से बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में दी गई कोयले की ऊष्मा दर और जीसीवी। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार गणना की गई कोयले की कीमत कोयले की वास्तविक कीमत के बराबर नहीं होगी और इसलिए, कोयले की ऐसी कीमत पर गणना किए गए कानून में परिवर्तन के लिए मुआवजा विक्रेता की आर्थिक स्थिति को उसी स्तर पर बहाल नहीं करेगा जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था।

107. सी. ई. आर. सी. ने आगे पाया है कि बोली में दिया गया एस. एच. आर. परीक्षण शर्तों के तहत है और वास्तविक एस. एच. आर. से भिन्न हो सकता है। सीईआरसी

विशेष रूप से देखा गया है कि व्यापक हितधारकों के परामर्श के बाद, सी. ई. आर. सी. ने 2014 के टैरिफ विनियमों में एस. एच. आर. मानदंडों को निर्दिष्ट किया है। इसलिए, यह पाया गया कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा सुझाए गए अन्य मापदंडों के बजाय विनियमों में निर्दिष्ट एस. एच. आर. को एक संदर्भ बिंदु के रूप में लेना उचित होगा।

108. सी. ई. आर. सी. ने आगे पाया कि सी. ई. आर. सी. मानदंड लागू होते हैं

अवधि 2009-14 और 2014-19 300 मेगावाट के लिए मानदंड प्रदान नहीं करते हैं। इकाइयाँ, लेकिन क्रमशः 6.5% और 4.5% के क्षरण कारक के लिए प्रदान करते हैं [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिजाइन गर्मी दर के ऊपर और ऊपर गर्मी दर की ओर। सी. ई. आर. सी. ने पाया कि चूंकि डिजाइन गर्मी दर 2211 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे थी, इसलिए सकल

2009-14 और 2014-19 की अवधि के लिए ऊष्मा दर क्रमशः 2355 किलो कैलोरी/kWh (2211 x 1.065) और 2310 किलो कैलोरी/kWh (2211 x 1.045) हो गई। इसलिए सी. ई. आर. सी. ने निर्देश दिया कि कानून में बदलाव के तहत मुआवजे के उद्देश्य से कोयले की खपत की गणना के लिए 2009-14 अवधि के दौरान 2355 के. सी. एल./कि. डब्ल्यू. एच. और 2014-19 अवधि के दौरान 2310 के. सी. एल./कि. डब्ल्यू. एच. या वास्तविक एस. एच. आर., जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा।

109. सी. ई. आर. सी. के इन निष्कर्षों की विद्वानों द्वारा पुष्टि की गई है।

ए. पी. टी. ई. एल. ने 16 जुलाई 2021 को अपने फैसले में कहा। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने इस प्रकार देखा:

" 8.8 हम सी. ई. आर. सी. द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमत हैं। एफ. एस. ए. के तहत संविदात्मक उपचार के लिए अपीलार्थी को बर्खास्त करना, जब अपीलार्थी के दावे की उत्पत्ति पी. पी. ए. के तहत कानून में परिवर्तन है, नहीं होगा। उचित है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी को कम आपूर्ति या श्रेणी में कमी के कारण कोयला कंपनी से कोई प्रोत्साहन या मुआवजा प्राप्त होता है, तो इस तरह के मुआवजे को प्रत्यर्थी द्वारा देय कानूनी मुआवजे में परिवर्तन के विरुद्ध समायोजित/जमा किया जाएगा।

एम. एस. ई. डी. सी. एल. "

110. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने 14 सितंबर को अपने फैसले में

2020 अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (ए. पी. एम. एल.) बनाम के मामले में 2019 की अपील No.182 में। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण

कंपनी लिमिटेड (2021 की सिविल अपील संख्या 684 में आक्षेपित) ने 2017 के मामले No.123 (JSW एनर्जी लिमिटेड v. एम. एस. ई. डी. सी. एल.), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानूनी मुआवजे में परिवर्तन के उद्देश्य से सहायक खपत को वास्तविक या एम. वाई. टी. मानदंडों से कम माना जाना चाहिए। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने अभिनिर्धारित किया कि अपने पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य आयोग, एम. ई. आर. सी. होने के नाते, वर्तमान मामले में भी एस. एच. आर. के लिए इसी दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए था। यह पाया गया है कि एम. ई. आर. सी. के लिए सहायक उपभोग और एस. एच. आर. के लिए दो अलग-अलग सिद्धांतों को लागू करने का कोई कारण नहीं है, जब दोनों परिचालन मानदंड हैं और आयोग इन पर काम कर रहा था -

दोनों मामलों में एक ही पी. पी. ए.।

111. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने निम्नलिखित का भी उल्लेख किया है:

सी. ई. आर. सी. ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मामले में 16 मई, 2019 के अपने आदेश में यह टिप्पणी की।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड बनाम एमएसईडीसीएल और ए. एन. आर. (याचिका No.284/MP/2018):

" 52 .

यह उल्लेख करना उचित है कि इसी तरह की प्रस्तुतियाँ

प्रतिवादी, एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा विचार किया गया था

याचिका में आयोग No.88/MP/2018 और यह था दिनांकित 15.11.2018 आदेश द्वारा देखा गया कि SHR में दिया गया है

बोली परीक्षण स्थितियों के तहत है और वास्तविक से भिन्न हो सकती है

एसएचआर। इसलिए एस. एच. आर. लेना ही सही होगा।

प्रशुल्क विनियमों में एक संदर्भ के रूप में निर्दिष्ट

द्वारा सुझाए गए अन्य मापदंडों के बजाय बिंदु

एमएसईडीसीएल। यह भी माना गया कि बोली के रूप में एसएचआर

कोयले का निर्धारण करने के लिए दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जा सकता है।

के तहत राहत की गणना के उद्देश्य के लिए आवश्यकता

कानून में परिवर्तन "।

[जोर दिया

गया]

112. इसके बाद विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा कि एस. एच. आर. ने प्रस्तुत किया

बोली में बोली दिशानिर्देशों के अनुसार बोली मानदंड नहीं था। यह सी. ई. आर. सी. के निष्कर्षों से सहमत था कि टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट एस. एच. आर. एक संदर्भ बिंदु के रूप में था। इसने अभिनिर्धारित किया कि इसका उपयोग कोयले की कमी की आवश्यकता की गणना के लिए आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, उत्पादन करने वाली कंपनी को दिए जाने वाले कानून मुआवजे में परिवर्तन की गणना के लिए किया जा सकता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि बोली दस्तावेजों में उल्लिखित एस. एच. आर. के लिए कानून मुआवजे में परिवर्तन को इस तरह से जोड़ने से प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में नहीं लाया जा सकेगा जैसे कि स्वीकृत कानून परिवर्तन की घटना नहीं हुई थी।

113. जहाँ तक जीसीवी का संबंध है, सीईआरसी के मामले में

जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड (उपरोक्त) ने विशेष रूप से एम. एस. ई. डी. सी. एल. के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि जी. सी. वी. को जी. सी. वी. बैंड के मध्य मूल्य पर लिया जाना चाहिए जिसे

'एज़ बिल' आधार पर मापा जाने वाले जी. सी. वी. पर लागू किया जाना चाहिए। सी. ई. आर. सी. ने माना कि, के ग्रेड फिसलन के कारण

सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले पर जी. सी. वी. को 'बिल के रूप में' आधार पर विचार करना उचित नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आयोग के 2014 के प्रशुल्क विनियमों में जी. सी. वी. के मापन को 'जैसा प्राप्त हुआ' के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, यह उचित होगा यदि मुआवजे की गणना के लिए 'जैसा प्राप्त हुआ' आधार पर जी. सी. वी. पर विचार किया जाए।

कानून में बदलाव। सी. ई. आर. सी. के इस निष्कर्ष की पुष्टि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा की गई है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

114. अडानी पावर के मामले में विद्वान एपीटीईएल

महाराष्ट्र लिमिटेड (ए. पी. एम. एल.) (उपरोक्त) ने इस मुद्दे पर भी विचार किया है कि क्या सी. आई. एल. द्वारा कानून मुआवजे में बदलाव की गणना के लिए आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले का संदर्भ जी. सी. वी. "मध्य मूल्य" होना चाहिए।

एल. ओ. ए./एफ. एस. ए./एम. ओ. यू. में सुनिश्चित कोयला श्रेणी की जी. सी. वी. श्रेणी। विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने पाया कि यह एक तथ्य है कि पी. पी. ए. में या बोली दिशानिर्देशों में संदर्भ जी. सी. वी. के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं है जिसे केस 1 बोली परियोजनाओं में कानून के दावों में बदलाव के मामले में लागू किया जाना चाहिए जहां एस. एच. आर. या जी. सी. वी. बोली मापदंड नहीं है। हालाँकि, इसने माना कि कानून मुआवजे में परिवर्तन के लिए व्यापक सिद्धांत यह था कि उत्पादन करने वाली कंपनी को बदतर आर्थिक स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने अभिनिर्धारित किया कि घरेलू कोयले में कमी की मात्रा का आकलन करने और तदनुसार कानूनी मुआवजे में परिवर्तन की गणना करने के लिए जी. सी. वी. 'जैसा प्राप्त हुआ' उचित आधार होना चाहिए।

115. यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (संक्षेप में "सी एंड एजी") ने एमओपी को प्रस्तुत की गई "एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली स्टेशनों के ईंधन प्रबंधन" पर अपनी प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा था कि कोयले की गुणवत्ता मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की प्रकृति के कारण अंतर्निहित और साथ ही मानव निर्मित दुर्बलताएं हैं। कोयला और नमूने की त्रुटियाँ '। इसलिए सी एंड एजी ने एमओपी को सिफारिश की कि इन तरीकों की उचित समीक्षा करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा मूल्य निर्धारण और एमओपी से सीईआरसी के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया था

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रकाश। अतः एमओपी ने सी. ई. ए. को 28 जून, 2017 को एक पत्र भेजा। उक्त संचार में, एमओपी ने कहा था कि एनटीपीसी ने नमूने लेने में त्रुटि के मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

2014 के टैरिफ विनियमों के अनुसार जी. सी. वी. के मापन के लिए नमूने के स्थान को "जैसे दागे गए" से "जैसे प्राप्त हुए" के आधार पर बदलना, वैगनों से लिए गए नमूनों की गैर-सजातीय प्रकृति, "जैसे दागे गए" के बिंदु से "जैसे दागे गए" के बिंदु तक जी. सी. वी. का नुकसान और "ऑगर्स" के माध्यम से कोयले के नमूने लेने में कठिनाई। इसमें आगे कहा गया है कि एमओपी ने

उक्त मुद्दे पर सी. ई. आर. सी. के विचार भी मांगे। इसलिए सी. ई. आर. सी. ने एम. ओ. पी. से इस संबंध में सी. ई. ए. से परामर्श करने का अनुरोध किया था और तदनुसार मामला सी. ई. ए. को भेजा गया था।

116. सी. ई. ए. ने 17 अक्टूबर 2017 को अपने संचार में कहा कि

इस प्रकार:

" सी. ई. ए. में इस मुद्दे की जांच की गई है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद सी. ई. ए. ने आई. डी. 1 पर आयोजित बैठक में कोयले के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे सी. आई. एम. एफ. आर. और सी. पी. आर. आई. के विचार भी लिए हैं।

ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [वी. आर. गवई, जे.]

यह स्वीकार किया जाता है कि जी. सी. वी. का नुकसान मुख्य रूप से एक बिजली संयंत्र के अंदर "प्राप्त के रूप में" से "दागे जाने के रूप में" तक होता है। निम्नलिखित कारकों के कारण:

(i)

कोयले के नमूने के जी. सी. वी. में नमी का प्रभाव

वैगन टॉप

जैसा कि सी एंड

एजी ने कहा है, कोयले की विषम प्रकृति के कारण नमूने लेने में त्रुटियां हैं। इस मुद्दे पर सी. आई. एम. एफ. आर. और सी. पी. आर. आई. के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सीआईएमएफआर और सीपीआरआई दोनों

कोयले की विषम प्रकृति के कारण वैगन टॉप-बॉटम जी. सी. वी. में अंतर को स्वीकार किया, नमी की प्रवृत्ति नीचे और ऊपर की परत के संपर्क में रहने के कारण वातावरण।

सी. ई. ए. का मानना है कि वैगन शीर्ष कोयले के जी. सी. वी. माप से वैगन के निचले हिस्से में नमी के स्टील होने और कोयले के परिवहन के दौरान वैगन शीर्ष से नमी के नुकसान के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक जी. सी. वी. मूल्य मिलेगा। हालांकि, जी. सी. वी. में नुकसान मौसमी भिन्नताओं के अनुसार अलग-अलग होगा।

बिजली संयंत्र के अंदर कोयले के भंडारण के दौरान जीसीवी में नुकसान

((ख)

सी. ई. ए. का विचार है और कई राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है।

और अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में कहा गया है कि कोयले के भंडार में जी. सी. वी. का नुकसान होता है जहां कोयले को बिजली संयंत्र के अंदर संग्रहीत किया जाता है, मुख्य रूप से ऑक्सीकरण और मौसम प्रभाव के कारण। इसके अलावा, अधिकांश

कोयले के लंबे भंडारण के दौरान जी. सी. वी. में नुकसान भंडारण की प्रारंभिक अवधि में होता है, ज्यादातर अस्थिर कोयले में नुकसान के कारण होता है।

सामग्री।

(iii) बिजली संयंत्र के अंदर संचालन के दौरान जी. सी. वी. में कमी

सी एंड एजी ने अपनी प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में देखा है कि कोयले का जीसीवी 'बिल के रूप में' चरण से उत्तरोत्तर कम हुआ है

'एज़ फायर्ड' स्टेज तक।

यह

स्वीकार किया जाता है कि बिजली संयंत्र के अंदर कोयले को संभालने में अनलोडिंग पॉइंट से लेकर बंकरिंग

पॉइंट तक मामूली अपरिहार्य नुकसान होते हैं। जी. सी. वी. में नुकसान मुख्य रूप से कोयला वाहक और स्थानांतरण बिंदुओं के आसपास उपयोग किए जाने वाले धूल दमन उपायों, वाष्पशील पदार्थ में नुकसान के कारण हो सकता है।

कोयले आदि की पेराई के दौरान।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ई. ए. ने विभिन्न राज्य नियामकों द्वारा लिए गए विचारों की भी जांच की है

उत्पादकों को अनुमत शुल्क के उद्देश्य से इस तरह के नुकसान पर विचार करने के लिए। हालाँकि, सी. ई. ए. का लक्ष्य अलग-अलग संयंत्रों, मौसम और कोयले की अलग-अलग विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग होगा।

इस राय का कि एक गैर-पिट हेड स्टेशन के लिए 85-100 किलो कैलोरी/किग्रा के अंतर को वैगन पर मापा गया जीसीवी का नुकसान माना जा सकता है

बॉयलर में कोयले के उत्सर्जित होने तक ऊपर।

117. 18 अक्टूबर 2017 के शुद्धिपत्र के माध्यम से, अंतिम वाक्य में, वैगन टॉप शब्दों के बाद, "उतराई बिंदु पर" शब्द जोड़े गए थे।

118. सी. ई. ए. ने 21 सितंबर 2017 को सी. आई. एम. एफ. आर. और सी. पी. आर. आई. जैसी कोयले के क्षेत्र में विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ बैठक करने के बाद उपरोक्त सलाह दी थी। इसने उत्पादकों को अनुमत शुल्क के उद्देश्य से इस तरह के नुकसान पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्य नियामकों द्वारा लिए गए विचारों की भी जांच की है। यह विचार करते हुए कि किस समय मार्जिन को जी. सी. वी. का नुकसान माना जा सकता है, सी. ई. ए. ने माना

120. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि दो विशेषज्ञ निकायों यानी सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने समवर्ती रूप से आयोजित किया है। अभिलेख पर सामग्री, कि एस. एच. आर. और जी. सी. वी. के कारकों पर विनियमों या वास्तविक, जो भी कम हो, के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। सीईआरसी के रूप में

साथ ही राज्य नियामक निकायों ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद संबंधित शुल्क विनियमों में एसएचआर मानदंडों को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा, जहां तक जी. सी. वी. का संबंध है, सी. ई. ए. ने राय दी है कि गैर-पिट हेड स्टेशन के लिए 85-100 के. सी. एल./कि. ग्रा. के मार्जिन को बॉयलर में कोयले के दहन के बिंदु तक वैगन टॉप पर मापा गया जी. सी. वी. का नुकसान माना जा सकता है।

121. इस संबंध में, हम रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। की स्थिति महाराष्ट्र और अन्य।

" 38. एम. ई. आर. सी. एक विशेषज्ञ निकाय है जिसे नियम और शर्तों सहित नियम बनाने का कर्तव्य और कार्य सौंपा गया है।

9 (2019) 3 एस. सी. सी. 352 ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

शुल्क के निर्धारण के लिए। न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रकट मामले में कदम उठा सकता है।

प्रक्रियाएँ या उन कारकों को ध्यान में रखना जो इसे अनिवार्य मानते हैं कानून द्वारा विचार करने के लिए या बाहरी विचारों पर टैरिफ के अपने निर्धारण को स्थापित किया है, न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

हालाँकि, यह न्यायालय के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है कि वह एक निर्णय के लिए अपने स्वयं के निर्धारण को प्रतिस्थापित करे जो एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा भौतिक परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद किया गया था। 39. एसोसिएशन में औद्योगिक विद्युत उपयोगकर्ता बनाम। की स्थिति

एपी. [एसोसिएशन। औद्योगिक विद्युत उपयोगकर्ता बनाम। ए. पी. राज्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 711] इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

शुल्कों का निर्धारण और इस प्रकार रखा गया: (एस. सी. सी. पी. 717, पैरा 11)

" 11. हम उच्च न्यायालय [एस. भारत] से भी सहमत हैं।

कुमार बनाम. एपी राज्य, 2000 एससीसी ऑनलाइन एपी 565: (2000) 6 ए. एल. डी. 217] कि शुल्क निर्धारण के संबंध में किसी मामले में न्यायिक समीक्षा किसी अपीलीय प्राधिकरण की तरह नहीं होनी चाहिए।

अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

संविधान। उच्च न्यायालय को केवल इस बात से संतुष्ट होना है कि आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है और जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि इसका निर्णय मनमाना या अवैध या अधिनियम के विपरीत है, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। शुल्क तय करना और क्रॉस-सब्सिडी प्रदान करना अनिवार्य रूप से नीति का विषय है और आम तौर पर एक अदालत नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से बचती है जब तक कि

प्रयोग मनमाना या कानूनी रूप से बुरा है। "

122. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विभिन्न विशेषज्ञ निकाय

सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. को शामिल करने के बाद

विभिन्न प्रासंगिक कारकों ने आई. आर. और जी. सी. वी. के संबंध में इस मुद्दे को तय किया है। इतना ही नहीं, बल्कि एक अन्य विशेषज्ञ निकाय यानी सी. ई. ए. ने सलाह दी है कि जी. सी. वी. मूल्य को न केवल 'प्राप्त होने पर' लिया जाना चाहिए

एन 'एज फायर्ड' आधार।

123. हाल ही में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस मामले में कहा: नारायण शर्मा बनाम भारत संघ "ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय 3 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति होनी चाहिए और जब तक यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रत्यक्ष रूप से मनमाने और अवैध हैं, तब तक इस न्यायालय के लिए विशेषज्ञ निकायों के साथ अपने विचारों को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।

124. यह हमें तीसरे मुद्दे के साथ छोड़ देता है कि क्या एम. ई. आर. सी. ने कानून में बदलाव के उद्देश्य से ऐसा मानना सही था। क्षतिपूर्ति, घरेलू लिंकेज कोयले में कमी का आकलन कोयले की आपूर्ति को (1) एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. के तहत सी. आई. एल. द्वारा उठाव के लिए प्रस्तावित कोयले की वास्तविक मात्रा और (2) संबंधित वर्ष के लिए एन. सी. डी. पी. 2013 में न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा के रूप में मानते हुए किया जाएगा।

125. निर्विवाद रूप से, एन. सी. डी. पी. 2007 के अनुसार, जहां तक आई. पी. पी./सी. पी. पी. और उर्वरक क्षेत्र सहित बिजली उपयोगिताओं का संबंध है,

एमओसी ने सीआईएल द्वारा घोषित/अधिसूचित की जाने वाली निर्धारित कीमतों पर सीआईएल द्वारा एफएसए के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की मानक आवश्यकता के अनुसार मात्रा का आश्वासन दिया था। इकाइयाँ/बिजली संयंत्र, जो अभी तक थे जिन कोयले की आवश्यकताओं का आकलन और स्वीकार पहले ही एम. ओ. सी. द्वारा किया जा चुका है और अनुमोदन किए गए लिंकेज/एल. ओ. ए. के साथ-साथ भविष्य की प्रतिबद्धताओं को भी उक्त नीति में शामिल किया जाना था। एन. सी. डी. पी. 2007 के पैरा 5 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोयले की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि संभव हो तो सी. आई. एल. को समय-समय पर कोयले का आयात करना पड़ सकता है। सी. आई. एल. को अपने समग्र मूल्य को तदनुसार समायोजित करना था। एक स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि यदि आवश्यक हो तो आयात का सहारा लेकर भी एफ. एस. ए. के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करना सी. आई. एल./कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।

126. हालांकि 2013 में कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण एम. ओ. सी. ने संकेत दिया था कि सी. आई. एल. आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो सकती है

एसीक्यू का 60 से 65 प्रतिशत से अधिक। इसलिए, भारत संघ ने महसूस किया कि घरेलू कोयला लिंकेज (एल. ओ. ए.) के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप डेवलपर्स और डिस्कॉम्स के बीच पहले से ही किए गए पी. पी. ए. को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए आयातित कोयले का उपयोग करना पड़ सकता है। 127. सी. सी. ई. ए. ने इस मुद्दे पर विचार किया और निर्णय लिया कि आयातित कोयले की उच्च लागत को पारित करने की अनुमति दी जाएगी। एम. ओ. पी. द्वारा सी. ई. आर. सी. को संबोधित 9 मई 2013 के पत्र से यह स्पष्ट है।

128. सी. ई. आर. सी. ने भी इस मुद्दे पर विचार किया। इसने नोट किया कि एफ. एस. ए. के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करना सी. आई. एल. की पूरी जिम्मेदारी है।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

सीईआरसी द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार पास-थ्रू के लिए विचार किया जाए। संचार में कहा गया है कि सरकार के निर्णय के अनुसार, आयात/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की अधिक लागत होगी एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. में दर्शाई गई मात्रा में कमी की सीमा तक सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर पारित किए जाने के लिए माना जाता है।

131. पैराग्राफ 6.1 में एमओपी द्वारा जारी 28 जनवरी 2016 की टैरिफ नीति में भी विशेष रूप से इस स्थिति को नोट किया गया है और कहा गया है कि

132. निर्विवाद रूप से, एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) के मामले के साथ-साथ अदानी राजस्थान मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा है कि कानून में परिवर्तन के कारण, उत्पादन करने वाली कंपनियां मुआवजे की हकदार थीं ताकि पार्टी को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल किया जा सके जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था। यदि कानून में बदलाव नहीं हुआ होता, तो उत्पादन कंपनियां एफ. एस. ए. के तहत सी. आई. एल./कोयला कंपनियों द्वारा आश्वासन के अनुसार आपूर्ति की हकदार होतीं।

133. डिस्कॉम्स द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि

यदि [2023] 8 एस. सी. आर. में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी तो बल आकस्मिकता लागू नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ऊपर) के साथ-साथ अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में, कानून में परिवर्तन के आधार पर बरकरार रखा गया है।

134. डिस्कॉम्स का यह तर्क कि अडानी राजस्थान मामला (ऊपर) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में, राजस्थान राज्य ने कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया था और यह कि यह एफ. एस. ए. का मामला नहीं था, हमारे विचार में, तथ्यहीन है। वर्तमान मामले में भी, एन. सी. डी. पी. 2007 ने मानक मूल्य के ईंधन/कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया था।

135. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन सिद्धांत कहा गया है।

(ऊपर) इस प्रकार:

" 10. अनुच्छेद 13.2 एक अंतर्निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत है जो कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति देता है और जो

मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से, प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह होगा कि इस खंड द्वारा एक कल्पना बनाई गई है, और पार्टी को उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात् पार्टी को दिया जाना चाहिए।

सिविल कानून में समझे गए पुनर्स्थापन का लाभ।

136. निर्विवाद रूप से, ए. पी. एम. एल. का दावा कानून में परिवर्तन के आधार पर है। डिस्कॉम्स, जो राज्य के साधन हैं, से सरकार के रुख के विपरीत बहस करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जनरेटर कानून में बदलाव के आधार पर खुले बाजार से आयात या खरीदे जाने के लिए आवश्यक कोयले के लिए गुजरने के हकदार होंगे।

137. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. जी. रामचंद्रन ने यह भी प्रस्तुत किया है कि यद्यपि कानून में परिवर्तन की घटना 31 जुलाई 2013 की है, लेकिन विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने 1 अप्रैल 2013 से इसे लागू करने में गलती की है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून में परिवर्तन 12 वीं महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के शेष चार वर्षों के लिए लागू किया गया है।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

139. डिस्कॉम्स की ओर से उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि यदि जनरेटरों को मुआवजे का दावा करने की अनुमति दी जाती है विनियमों के अनुसार वास्तविक एसएचआर या एसएचआर, जो भी कम हो, उन्हें अपनी अक्षमता का लाभ उठाने की अनुमति देगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. एच. आर. जितना कम होगा, मशीन की दक्षता उतनी ही अधिक होगी और इसलिए बिजली का उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत, जब मशीन है

अक्षम, एसएचआर अधिक है और बिजली उत्पादन कम है। एस. एच. आर. न केवल मशीन की दक्षता पर बल्कि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर है। अन्य कारकों में से एक पीएलएफ है। इस संबंध में,

20 मई 2013 को सी. ई. आर. सी. द्वारा जारी वैधानिक सलाह का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसका प्रासंगिक हिस्सा पहले ही यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण

सी. आई. एल./कोयला कंपनियाँ, देश भर के उत्पादन स्टेशनों का पी. एल. एफ. बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस प्रकार, हमारे विचार में, इस संबंध में विवाद सारहीन है।

140. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न डिस्कॉम आत्म-विरोधाभासी रुख अपना रहे हैं। मेसर्स अदानी पावर लिमिटेड बनाम के बीच 2017 की याचिका संख्या 97 में। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्न।, द.

डिस्कॉम्स ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है:

" ए। पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 के तहत कानून में परिवर्तन के कारण राहत का निर्णय लेते समय सी. ई. आर. सी. टैरिफ विनियमों के अनुरूप बेहतर दक्षता मानकों पर विचार करने में खुशी हो सकती है जैसे कि न्यूनतम प्रकृति में उत्तरदाताओं के उपभोक्ताओं पर प्रभाव।

मेरी अदालत की रिपोर्टराहत (यदि दी जाती है), विचार करने के बाद पारित की जा सकती है

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

उक्त अवधि का वास्तविक प्रभाव होना चाहिए

विभिन्न कारकों के आधार पर गणना की जाती है अर्थात्

मानक प्रक्रियाओं पर आवश्यकता की मात्रा जैसे कि:

आई.

स्टेशन ऊष्मा दर पर विचार किया जाएगा

समय-समय पर सी. ई. आर. सी. नियमों के अनुसार वास्तविक डिजाइन गर्मी दर और मार्जिन का पता लगाना।

समय पर।

इसी तरह, सहायक खपत होगी

ii.

सी. ई. आर. सी. नियमों के अनुसार माना जाता है।

वैकल्पिक कोयले का जीसीवी प्रमाणित होगा।

iii.

तृतीय पक्ष नमूना एजेंसी द्वारा जिसके लिए माननीय आयोग को प्रावधान करना चाहिए

दिशा-निर्देश का पालन करें।

लक्षित पीएलएफ;

iv.

द्वारा उपयोग किए गए वास्तविक कोयले की सही तारीख

वी.

याचिकाकर्ता मासिक और वार्षिक आधार पर;

एमसीएल द्वारा प्रस्तावित कोयले की मात्रा जो

vi.

याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार किया गया था या नहीं लिया गया था;
उत्पादित बिजली की वास्तविक मात्रा

vii.

याचिकाकर्ता द्वारा

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में राहत के लिए याचिकाकर्ता के दावे की गणना उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की गणना, जैसा कि उसकी याचिका में कहा गया है, इसलिए अस्वीकार की जा सकती है क्योंकि यह सामान्य है।

और प्रकृति में अस्पष्ट।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने केवल पिछली अवधि तक सीमित प्रभाव का संकेत दिया है। हालांकि, उत्तरदाताओं

विनम्रतापूर्वक माननीय आयोग से अनुरोध है कि केवल

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम के बाद, पिछली अवधि के लिए ऐसे दावों को मंजूरी दें।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

के लिए एक सूत्र के साथ उपरोक्त पर विचार करना

भविष्य की अवधि "।

[जोर दिया

गया]

141. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम-यूएचबीवीएनएल के पास स्वयं

उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव के कारण राहत तय करने के लिए सी. ई. आर. सी. टैरिफ विनियमों के अनुरूप बेहतर दक्षता मानकों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि उत्तरदाताओं के उपभोक्ताओं पर प्रभाव न्यूनतम प्रकृति का हो। इसने वास्तविक डिजाइन गर्मी दर का पता लगाने के बाद एसएचआर को ध्यान में रखने के लिए किसी भी राहत के लिए भी अनुरोध किया है।

और समय-समय पर सी. ई. आर. सी. नियमों के अनुसार मार्जिन। इसी तरह, इसने यह भी अनुरोध किया है कि सहायक उपभोग पर सी. ई. आर. सी. विनियमों के अनुसार विचार किया जाए। जहां तक वैकल्पिक कोयले के जीसीवी का संबंध है, इसने आगे कहा है कि इसे थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

142. यह विवाद में नहीं है कि एस. एच. आर. का लेखा-परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

लगातार और जी. सी. वी. को तीसरे पक्ष की नमूना एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

143. यह ध्यान देने योग्य है कि एम. ई. आर. सी. स्वयं अपने क्रम में

2017 के मामले No.123 में दिनांक 7 मार्च 2018 (JSW v. एम. एस. ई. डी. सी. एल.) ने पूरी तरह से विरोधाभासी रुख अपनाया है। 7 मार्च 2013 के उक्त आदेश के अनुच्छेद 19.11 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव

" 19.11

पुनर्स्थापित करने के लिए सहायक उपभोग पर कानून

समान आर्थिक स्थिति के लिए जनरेटर जैसे कि कानून में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। द.

कानून में परिवर्तन सहायक पर लागू होगा।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार इकाई की खपत

आयोग द्वारा या वास्तविक रूप से, जो भी कम हो

परियोजना का शुल्क प्रतिस्पर्धी पर आधारित है

उपभोग मानक मूल्य पर होना चाहिए।

केवल अनुसूचित पीढ़ी के अनुरूप।

इसके अलावा, के संबंध में कानून में यह परिवर्तन

सहायक खपत में बिजली शामिल नहीं होगी।

उत्पादन की कर्मचारी कालोनियों के लिए खपत

स्टेशन "।

[जोर दिया

गया] [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

144. इस प्रकार, यह समझना मुश्किल है कि कैसे एम. ई. आर. सी. ने एक दृष्टिकोण में यह माना है कि सहायक उपभोग पर कानून में परिवर्तन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार या वास्तविक, कभी भी कम नहीं है, जब इसने दिनांक 7 मार्च 2018 को ए. पी. एम. एल. के मामले में इसे अस्वीकार कर दिया है।

145. हम एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए रुख का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

" 15. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें हमारे समक्ष अपीलों के अंतिम परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह केवल हमें यह बताने के लिए उपस्थित हो रहे थे कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद, इसने 2003 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को काफी हद तक पूरा किया है, जो कि बिजली है।

उत्पादन, विलयित होने के कारण, उत्पादन में परिणाम होना चाहिए

पहले की तुलना में कहीं अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता था। उन्होंने आग्रह किया

अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले नाजुक संतुलन को बाधित न करने के लिए, अर्थात् बिजली के उत्पादक या जनरेटर, क्रम में

कि वे बिजली संयंत्र स्थापित करें, एक उचित अधिकार के हकदार हों

लाभ का मार्जिन और उनकी पूंजी पर उचित लाभ, ताकि वे अधिक से अधिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित हों। यह उनके बीच प्रतिस्पर्धा के अनुरूप होना चाहिए, जो तब खुद को उचित शुल्क में बदल देता है जो बिजली के उपभोक्ताओं द्वारा देय होते हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने बिजली अधिनियम की धारा 3 पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि

सरकार समय-समय पर राज्य के साथ परामर्श करके एक राष्ट्रीय बिजली नीति और एक शुल्क नीति तैयार करेगी। सरकारें, और सत्ता के विकास के लिए प्राधिकरण

प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित प्रणाली।

उनके अनुसार, राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क

प्रकृति, सभी संबंधित लोगों के लिए बाध्यकारी है। यह, वास्तव में, आगे है धारा 61 (i) द्वारा मान्यता प्राप्त जिसके द्वारा उपयुक्त आयोग, शुल्कों के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए,

राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की भूमिका आगे भी देखी जा सकती है

धारा 63, जहाँ सभी के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा ऐसे मामलों में जहां एक
बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया।
केस नंबर में एड।

189 2013 का और 2014 का 140 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [वी. आर. गवई, जे.]

16. इसके अलावा, विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, अनुभाग 79 (4) यह भी एक ही दिशा में इंगित करता है, यह कहते हुए कि, के निर्वहन में

केंद्रीय आयोग अपने कार्यों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्देशित होगा। विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क नीति

धारा 3 के तहत प्रकाशित। उन्होंने हमें मंत्रिमंडल के पास भी भेजा।

आर्थिक मामलों की समिति ने समग्र रूप से मान्यता दी

घरेलू कोयले और नए कोयले के निर्माण में कमी मंत्रिमंडल के अनुसार जुलाई 2013 में जारी वितरण नीति

बाध्यकारी दिशाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि जनरेटर के रूप में स्वदेशी कोयले पर निर्भर बिजली दी गई है

अनुमान से कम कोयला, या तो अनुमति दी जानी चाहिए

कोयले का खुद आयात करें, या आयातित कोयले की खरीद करें

कोल इंडिया लिमिटेड, कीमत में अंतर को पारित किया जा रहा है

उनके द्वारा। उन्होंने आगे संशोधित का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया उसी उद्देश्य के लिए 28-1-2016 की शुल्क नीति।

[जोर दिया गया]

146. विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ हैं

उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि बिजली अधिनियम के अधिनियमन के लिए मुख्य विशेषताओं में से एक उत्पादन को अलग करना और स्वतंत्र रूप से कैप्टिव उत्पादन की अनुमति देना था। इस प्रकार, विद्वान महान्यायवादी ने एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में कहा कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद, बिजली अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को काफी हद तक पूरा कर लिया है। विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के बाद, कम बिजली उत्पादन के परिणामस्वरूप पहले की तुलना में कहीं अधिक बिजली का उत्पादन। विद्वान महान्यायवादी ने न्यायालय से बिजली अधिनियम, अर्थात् [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले नाजुक संतुलन को बाधित नहीं करने का आग्रह किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली के उत्पादक या जनरेटर, ताकि वे बिजली संयंत्र स्थापित कर सकें, लाभ के उचित अंतर और उचित लाभ के हकदार होंगे।

अपनी पूंजी पर वापस लौटें, ताकि वे अधिक से अधिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित हों। 147. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में यह तर्क देने की मांग की गई थी कि बिजली अधिनियम की धारा 63 के तहत एक मामले में, आयोग को केवल बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाना था, इस अदालत ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया। इसने माना कि वास्तव में, बिजली अधिनियम की धारा 62 और 63 शुल्क के 'निर्धारण' से संबंधित है, जो शुल्क को 'विनियमित' करने का हिस्सा है। इसने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में जहां धारा 63 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश स्थिति को कवर करते हैं,

केंद्रीय आयोग उन दिशानिर्देशों से बाध्य है और उसे अपने नियामक कार्यों का प्रयोग करना चाहिए।

148. भारत संघ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के खंड 4.7 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिन्हें एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में बाध्यकारी माना गया है, जो इस प्रकार है:

कानून के संबंध में खरीदार को बिजली बेचने के व्यवसाय से लागत या राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून में कोई बदलाव। आर. एफ. पी. बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लागू होने वाली तारीख को अलग से समायोजित किया जाएगा। कानून में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में,

उपयुक्त आयोग लागू होगा।

149. एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंजूरी दी है।

अडानी राजस्थान मामला (ऊपर)।

150. इस कानूनी स्थिति और भारत संघ द्वारा लिए गए रुख के बावजूद, डिस्कॉम्स एक ऐसा रुख अपना रहे हैं जो इस रुख के विपरीत है

भारत संघ का। एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) में भी इसकी मांग की गई थी।

डिस्कॉम्स द्वारा आग्रह किया जाना चाहिए कि कानून में परिवर्तन के कारण भी समायोजन की अनुमति नहीं होगी, जो तर्क पूरी तरह से था

अस्वीकार कर दिया। हमें ऐसे कई मामलों का पता चला है जिनमें नियामक निकाय और अपीलीय मंच द्वारा पारित समवर्ती आदेशों पर हमला किया जाता है। इस तरह की मुकदमेबाजी, वास्तव में, के उद्देश्य को समाप्त कर देगी

विद्युत अधिनियम। जैसा कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रमुख महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनियों में से एक है।

लिमिटेड। वी. अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के कारण राज्य विद्युत बोर्डों के प्रदर्शन में गिरावट थी।

151. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि डिस्कॉम्स द्वारा लिया गया रुख कि, क्योंकि उत्पादन से नुकसान हो रहा है

सी. आई. एल./कोयला कंपनियों द्वारा दायित्व को पूरा न करने के कारण कंपनियों को सी. आई. एल./कोयला कंपनियों के खिलाफ कानून में उनके लिए उपलब्ध उपचार के दायरे में लाया जाना पूरी तरह से अनुचित है। यह दावा एन. सी. डी. पी. 2013 द्वारा एन. सी. डी. पी. 2007 के परिवर्तन पर आधारित है, जो निर्विवाद रूप से 'कानून में परिवर्तन' शब्द द्वारा कवर किया गया है।

152. हाल ही में, यह न्यायालय, केंद्रीय भंडारण निगम बनाम के मामले में। अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड

(ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) और अन्य 2 "ने एक ही मुद्दे पर विरोधाभासी/अलग-अलग रुख/रुख अपनाने की राज्य की विभिन्न साधनों की प्रथा की निंदा की है।

153. वर्तमान मामले में, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने यह भी माना है कि

एस. एच. आर. और जी. सी. वी. को 'वास्तविक' या शुल्क विनियमों के अनुसार ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो भी कम हो और इस तरह, उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को भी संतुलित किया जाए।

154. यह हमें जी. एम. आर. (यानी 2021 की सिविल अपील No.6927) के मामले में उठाए गए अतिरिक्त मुद्दे से निपटने के लिए छोड़ देता है।

155. सी. ई. आर. सी. ने एस. एच. आर. और जी. सी. वी. पर अपने निष्कर्ष के अलावा विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा ही हुआ है।

ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पुष्टि की गई। सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ विद्वान ए. पी. टी. ई. एल., अनुच्छेद 8.3 की व्याख्या पर। 5 और 8. 8.3 पी. पी. ए. ने समवर्ती रूप से पाया है कि खरीदार ने नियत तिथि के भीतर भुगतान नहीं करके भुगतान में देरी की थी और इस तरह, जी. एम. आर. विलंब भुगतान अधिभार का हकदार था। हम तथ्य के उक्त समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

156. इसलिए, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। लंबित आवेदन, यदि कोई भी, निपटाया जाएगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस (सहायक: प्रांजल सिंह और राहुल राठी, एलसीआरएस)

1 2 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1398